अंतर्राष्ट्रीय व्यापार

7
अध्याय

वर्ष 2008 और 2009 के उठा-पटक वाले मंदीग्रस्त वर्षों में तमाम देशों में वैदेशिक व्यापार में वृद्धि ढह सी गई थी। व्यापार में यह गिरावट जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के मुकाबले कहीं अधिक तीव्र थी, वर्ष 2010 में ठहर गई थी और व्यापार की वृद्धि में वास्तविक सघउ वृद्धि की अपेक्षा अधिक तेजी से सुधार हुआ है। व्यापार वृद्धि में यह सुधार आंशिक रूप से सरकारों द्वारा दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहनों और पूर्ववर्ती वर्षों के निम्न आधार के कारण संभव हो सकी है। तथापि सुधार की मात्रा में विभिन्न देशों में काफी अधिक भिन्नता है और विश्व व्यापार अभी भी अपने संकटपूर्व की स्थिति से नीचे बना हुआ है। भारत, जिसने वैश्विक संकट का अच्छी तरह सामना किया, उन कुछेक देशों में से एक है, जिसने व्यापार में संकटकाल से पूर्व की ऊंचाई को छुआ है और यहां तक कि उससे आगे निकल गया है।

विश्व व्यापार

7.2 विश्व व्यापार में 2008 में 16 ट्रिलियन अमरीकी डालर से 2009 में 12.4 ट्रिलियन अमरीकी डालर तक की एकाएक और तेजी से गिरावट के बाद 2010 में प्रभावशाली सुधार हुआ। 2010 के पूर्वार्ध में विश्व व्यापार 7.03 ट्रिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया था जो 24 प्रतिशत की मूल्य वृद्धि है। विश्व व्यापार की मात्रा, जो 2009 में असाधारण रूप से 10.7 प्रतिशत तक गिर गई थी, में 2010 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक के जनवरी 2011 के अंक के मुताबिक 12 प्रतिशत का तेजी से सुधार आया है। (सारणी 7.1)

यह सुधार जहां आंशिक रूप से आधार प्रभाव के कारण है, वहीं विश्व व्यापार में 2009 में (–)0.6 प्रतिशत की ऋणात्मक से 2010 में 5.0 प्रतिशत की सकारात्मक तेजी को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए राजकोषीय प्रोत्साहनों का सहारा मिला। जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा उल्लेख किया गया है, विश्व व्यापार अपने संकट-पूर्व के रूझान से नीचे बना हुआ है और कुछ अर्थव्यवस्थाओं के मामले में, विशेषकर वे अर्थव्यवस्थाएं जो बैंकिंग संकट से प्रभावित हुई हैं, यह संकट-पूर्व के स्तरों से नीचे बना हुआ है। वर्ष 2010 में उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के व्यापार की मात्रा में वृद्धि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले

सारणी 7.1 : व्यापार में वृद्धि संबंधी रूझान (प्रतिशत परिवर्तन)

(प्रतिशत)

			निरूपण	
	2009	2010	2011	2012
विश्व व्यापार की मात्रा (माल एवं सेवाएं)	–10.7	12.0	7.1	6.8
आयात				
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	–12.4	11.1	5.5	5.2
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	–8.0	13.8	9.3	9.2
निर्यात				
विकसित अर्थव्यवस्थाएं	–11.9	11.4	6.2	5.8
उभरती एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	–7.5	12.8	9.2	8.8

स्रोत: आईएमएफ; डब्ल्यू ई ओ, जनवरी 2011

अधिक सुदृढ़ थी, ठीक उसी प्रकार जैसे 2009 में उनकी गिरावट कम तीव्र थी।

7.3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुसार, विश्व व्यापार की मात्रा के 2011 और 2012 में क्रमशः 7.1 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत पर मंद रहने की आशा है। तथापि, उभरती हुई और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार की वृद्धि के 2011 और 2012 में अधिक मजबूत रहने की आशा है।

व्यापार ऋण: अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य

7.4 वैश्विक आर्थिक संकट ने जहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला, वहीं आपूर्ति पक्ष में यह दर्शाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वित्तीय संकट ने व्यापार ऋण की उपलब्धता को कम किया होगा। इसके परिणामस्वरूप व्यापार की मात्रा में कमी आ सकती थी, जो अन्यथा मांग स्टॉक में भी कम हुआ होता। इस प्रकार व्यापार ऋण की कमी ने मंदी को अधिक हानिकारक और दीर्घावधिक बनाया होता। विश्व व्यापार का लगभग 90 प्रतिशत कथित रूप से किसी ने किसी रूप में व्यापार वित्त या बीमा पर निर्भर रहता है, जिसमें इस बाजार का कुल आकार 2008 में 10 से 12 ट्रिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप व्यापार वित्त नकदी में 25 बिलियन अमरीकी डालर की कमी होने का अनुमान लगाया है, जबकि विश्व बैंक ने अनुमान लगाया कि व्यापार वित्त में कमी व्यापार में 10 से 15 प्रतिशत की कमी का कारण थी।

7.5 राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान ब्यूरो (एनबीईआर)के एक ताजा अध्ययन में यह साक्ष्य दिया गया है कि प्रतिकूल ऋण की स्थितियां एक महत्वपूर्ण माध्यम थीं, जिनके माध्यम से वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट ने व्यापार की मात्रा को प्रभावित किया। संयुक्त राज्य अमरीका के बाजार का उदाहरण देते हुए, अध्ययन में कहा गया है कि उच्चतर अंतः बैंक दरों और इस प्रकार तंग ऋण उपलब्धता वाले देशों ने अमरीका को कम निर्यात किया। इस प्रकार न केवल अमरीकी मांग में गिरावट से अपितु अमरीका में ऋण की स्थिति तंग होने, जिसके परिणामस्वरूप अमरीका को निर्यात करने वाली फर्मों के लिए व्यापार वित्तपोषण की लागत में वृद्धि हुई, ने ऋण की उच्च लागत वाले देशों में, अधिक बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की होंगी।

7.6 जून 2010 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा किया गया एक अध्ययन संकटपूर्व और संकट-पश्च व्यापार पर व्यापार वित्त के प्रभाव की दृष्टि से एक विविधतापूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करता है जो आरंभिक प्रभाव को इंगित करता है। अध्ययन में इस बात को उजागर किया गया है कि व्यापार वित्त की उपलब्धता का 'सामान्य' परिस्थितियों, अर्थात् संकट से बाहर की अवधियों में निर्यात पर सीमित प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है। तथापि, मार्च 2010 में एक आईएमएफ -बीएएफटी (बैंकर्स एसोसिएशन फॉर फाइनेंस एंड ट्रेड) सर्वेक्षण का यह विचार है कि वैश्विक मांग में गिरावट, व्यापार में गिरावट का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, जिसके बाद व्यापार वित्त पोषण में कमी का स्थान है। 2010 के मध्य में इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स (आईसीसी) के एक सर्वेक्षण, जिसमें 75 देशों में स्थित 161 बैंकों को शामिल किया गया था, में भी बताया गया है कि व्यापार वित्त की लागतें संकट-पूर्व अवधि के मुकाबले बहुत अधिक ऊंची बनी हुई है। इससे निर्यातकों के लिए वहनीयता की समस्या उठ खड़ी हुई है।

7.7 जी-20 व्यापार वित्त विशेषज्ञ समूह की अप्रैल 2010 की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2009 के दूसरी छमाही और 2010 की पहली तिमाही के दौरान, इस बात के साक्ष्य हैं कि अल्पावधिक व्यापार वित्त बाजारों में आम तौर पर सुधार आया है। वृहत उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में लेटर ऑफ क्रेडिट के औसत मूल्य एक वर्ष पूर्व 150-250 आधार-बिन्दु से घट कर 70-150 आधार बिन्दु रह गए हैं, और अनेक विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बाजार तेजी से सामान्य हालत की ओर लौट रहे हैं। तथापि, यह समुत्थान सार्वभौमिक नहीं रहा है और अनेक क्षेत्रों में ऐसे बाजार हैं, विशेषकर अफ्रीका में, जो तंगी से जूझ रहे हैं। बाजार स्रोत बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अथवा वृहत सम्पूर्ण अफ्रीका में फैले बैंक, ऐसे देशों में, जिन्हें अफ्रीका में कम जोखिम वाले देश माना जाता है, एक लेटर ऑफ क्रेडिट को समर्थित करने के लिए 200 से 320 आधार बिन्दु प्रभारित करना जारी रखे हुए हैं। एशिया और मध्य अमरीका के न्यून आय वाले देश बेहतर स्थिति में जान पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में, नकदी की स्थिति लगभग सामान्य हो गई है, परन्तु अभी भी व्यापारियों की ऋण-सामर्थ्य की स्थिति में आम गिरावट के साथ-साथ वाणिज्यिक बैंकों की ज्यादा से ज्यादा जोखिम से बचने की प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप बाजार अंतराल बना हुआ है। एक रोचक घटनाक्रम संभावित रूप से संरचित व्यापार वित्त की दिशा में स्थाई रूप से बढ़ना है। इस वित्तीय संकट ने जोखिम के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाई है, जिससे परम्परागत खुला खाता वित्तपोषण की अपेक्षा मध्यस्थतायुक्त व्यापार वित्त की सापेक्षिक मांग में बढ़ोतरी हुई है। वास्तव में, हाल के अनुमान दर्शाते हैं कि 2009 में मध्यस्थतायुक्त व्यापार वित्त (बैंक सहायताप्रदत्त) का स्तर खुला खाता लेनदेनों की अपेक्षा अधिक है, जिससे खुला खाता वित्तपोषण के प्रति दीर्घावधिक रुझान में बदलाव आया है।

7.8 जी-20 ने सिओल शिखर बैठक (नवम्बर 2010) के दौरान जारी अपनी विज्ञप्ति में विकासशील देशों, विशेषकर न्यून-आय वाले देशों में व्यापार वित्त की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता दुहराई है। इस संबंध में, जी-20 के मंत्रिगण विकासशील देशों के समर्थन में व्यापार वित्त कार्यक्रमों, का मूल्यांकन करने और व्यापार वित्त पर विनियामक व्यवस्थाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करने पर सहमत हुए हैं। जी-20 ट्रेड फाइनेंस एक्सपर्ट ग्रुप को डब्लयूटीओ एक्सपर्ट्स ग्रुप ऑन ट्रेड फाइनेंस और ओईसीडी एक्सपोर्ट क्रेडिट ग्रुप के साथ न्यून आय वाले देशों में व्यापार वित्त की वर्तमान आवश्यकता का आकलन करने का अधिदेश दिया गया है और यदि कोई अंतर का पता चलता है तो यह निम्न आय वाले देशों में इसकी उपलब्धता बढ़ाने के उपाय तैयार करेगा और उनको समर्थित करेगा।

7.9 बीएएफटी-आईएफएसए (बैंकर्स एसोसिएशन ऑफ ट्रेड फाइनेंस और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज एसोसिएशन की एकीकृत संस्था) ने जून 2008 में व्यापार वित्त जोखिम का उपशमन करने हेतु मास्टर पार्टनरशिप एग्रीमेंट (एमपीए) की घोषणा की। एमपीए समूचे विश्व भर में बैंकों और उनके प्रति पक्षों द्वारा प्रयोग के लिए देश और बैंक व्यापार वित्त से संबंधित जोखिम को खरीदने और बेचने को सुविधाजनक बनाने के लिए एक उद्योग मानक है। यह दस्तावेजों के लेनदेन को सरलीकृत करने, कानूनी लागतों को कम करने, दक्षता बढ़ाने और व्यापार को बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

7.10 बहुपक्षीय संगठनों ने व्यापार वित्त की उपलब्धता को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक समर्थक उपाय शुरू किए हैं। यूरोपीयन बैंक फॉर रिकन्शट्रक्शन एंड डवलपमेंट्स ट्रेड फेशिलिटेशन प्रोग्राम द्वारा कुल 550 मिलियन यूरो के 850 से अधिक विदेशी व्यापार लेनदेनों को सहायता प्रदान की गई जिसमें व्यापार वित्त बाजार को अतिरिक्त लाभ उपलब्ध कराए गए। एशियाई विकास बैंक के ट्रेड फाइनेंस फेसिलिटेशन प्रोग्राम की ऋण प्रदायगी सीमा बढ़ाकर 1 बिलियन अमरीकी डालर की गई। 2009 में, टीएफएफपी ने व्यापार में 2 बिलियन अमरीकी डालर की सहायता की जो 2008 की तुलना में 300 प्रतिशत की वृद्धि है। इंटरनेशनल फाइनेंस कोरपोरेशन ने अपने वैश्विक व्यापार वित्त कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2010 में 3.46 बिलियन अमरीकी डालर की गारंटियां जारी की जो पूर्व वर्ष की तुलना में 44 प्रतिशत की वृद्धि है।

7.11 निर्यात पूर्व वित्त पोषण और निर्यात ऋण एजेन्सियों द्वारा समर्थित ऋणों ने 2010 के व्यापार वित्त बाजारों में अहम भूमिका निभाई है। समूचे विश्व में राष्ट्रीय सरकारों ने व्यापार वित्त क्रियाकलापों को वित्त सहायता देने के लिए युद्धस्तर पर कार्यनीतियां ईजाद की हैं, उनमें से कुछ संबंधित निर्यात ऋण एजेन्सियों या विकासात्मक संस्थाओं के माध्यम से हैं। (देखें बाक्स 7.1)

व्यापार ऋण: भारतीय परिदृश्य

7.12 वैश्विक संकट और निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय रिजर्व बैंक ने 270 दिन तक के लदान-पूर्व रुपया निर्यात ऋण और 180 दिन तक के लदान-पश्च रुपया निर्यात ऋण पर ब्याज दर सीमा बेंचमार्क मूल उधार दर (बीपीएलआर) से नीचे 250 आधार बिन्दु तक घटा दी। यह सुविधा 30 जून, 2010 तक उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने 2010-11 के अपने केन्द्रीय बजट में हस्तशिल्प, कालीन, हथकरघा और लघु तथा मझौले उद्यमों जैसे कतिपय रोजगारपरक निर्यात क्षेत्रों के लिए लदान-पूर्व और लदान-पश्च रुपया निर्यात ऋण पर 2 प्रतिशत की ब्याज दर आर्थिक सहायता का विस्तार 31 मार्च 2011 तक कर दिया है। 9 अगस्त 2010 को ब्याज दर आर्थिक सहायता योजना का विस्तार चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण, फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण, इंजीनियरिंग वस्तुओं और कपड़े पर 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2011 तक कर दिया। बेस दर के लागू होने से, रुपया

बॉक्स 7.1 : चुनिंदा देशों में व्यापार ऋण में कमी के संबंध में नीतिगत उपाय

व्यापार ऋण के संबंध में कुछ चुनिंदा देशों के नीतिगत उपाय निम्नलिखित थे:

- यू एस एक्जिम बैंक निर्यात-आयात ने उभरते हुए बाजारों को अमरीकी वस्तुओं के निर्यात में सहायता के लिए नए अल्पावधि व्यापार वित्त सुविधाओं में 4 बिलियन अमरीकी डालर और मध्यम-और दीर्घावधि व्यापार वित्त सुविधाओं में 8 बिलियन अमरीकी डालर उपलब्ध कराने के एक कार्यक्रम की घोषणा की। इसी प्रकार, चीन ने चाइना-एक्जिम बैंक के माध्यम से उभरते हुए बाजारों को चीनी वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए अल्प, मध्यम और दीर्घावधि की व्यापार वित्त सुविधाएं उपलब्ध कराईं।
- फेडरल रिजर्व, यूएसए ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में विदेशी मुद्रा नकदी को रखने के लिए यूरोपीयन सेंट्रल बैंक और विभिन्न देशों के केन्द्रीय बैंकों के साथ मुद्रा विनिमय सुविधाओं की घोषणा की।
- यूके सरकार ने लघु और मध्यम कम्पनियों को कुल 20 बिलियन पौंड के बैंक ऋणों को गारंटी देने की योजनाओं की घोषणा की।
- जर्मनी ने बैंकिंग प्रणाली में विश्वास पैदा करने और इसमें नकदी लाने के लिए 480 बिलियन यूरो (672 बिलियन अमरीकी डालर) के वित्तीय सेक्टर राहत पैकेज की घोषणा की।
- सेन्ट्रल बैंक ऑफ रशिया ने छह माह तक बिना वांछित जमानती के वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देने की योजनाओं की घोषणा की। इसके अतिरिक्त, सेन्ट्रल बैंक ने 2009 के अंत तक नेशेकोनोमो बैंक को 50 बिलियन अमरीकी डालर की ऋण श्रृंखला प्रदान की।
- हांगकांग सरकार एसएआर की सरकार ने लघु और मध्यम उद्यमों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण की अधिकतम गारंटी अवधि दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष करने का प्रस्ताव किया है।
- जापानी सरकार ने आईएफसी और एडीबी के निकट सहयोग से विकसित की जाने वाली, 1.0 बिलियन अमरीकी डालर व्यापार वित्त सुगमीकरण कार्यक्रम अभिक्रम की घोषणा की।
- ब्राजील की ऋण एजेंसी बांको नेशनल डि डेसेन्वोल्वीमेंटों इकोनोमिको इ सोशल ने ब्राजीली कंपनियों के लिए 6 बिलियन डालर की घोषणा की;
- ब्राजीलियाई सेन्ट्रल बैंक ने पुनर्खरीद खंडों सहित बैंकों को 1 बिलियन अमरीकी डालर की नीलामी की (जो इसे व्यापार ऋण श्रृंखलाओं के लिए इस्तेमाल करेंगे)।
- कोलम्बिया और वेनेजुएला ने दोनों देशों के बीच सीमा आर-पार व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से एक विशेष निधि की स्थापना के लिए प्रत्येक ने 100 मिलियन अमरीकी डालर की प्रतिबद्धता की।

निर्यात ऋण पर प्रभारित उधार दरें 1 जुलाई 2010 से विनियंत्रित कर दी गईं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह निर्देश दिए हैं कि बैंक उपलब्ध आर्थिक सहायता द्वारा ऊपर विनिर्दिष्ट सेक्टरों में बेस दर के अनुसार प्रभार्य दर घटा सकते हैं, भले ही निर्यातकों को प्रभारित ब्याज दर 7 प्रतिशत की सीमा के अधीन, बेस दर से नीचे चली जाए।

7.13 अंतर्राष्ट्रीय ऋण बाजारों में व्याप्त कठिन वित्तपोषण स्थितियों और उधारदाता संस्थाओं की जोखिम से बचने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप, 2008-09 के दौरान भारत को अल्पावधि व्यापार ऋण की सकल अंतर्प्रवाह 2007-08 की अपेक्षा कम था। 2008-09 के दौरान अल्पावधि व्यापार ऋण का सकल अंतर्प्रवाह 41.8 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया, जबकि अदायगियां (अल्पावधि व्यापार ऋण का बहिर्प्रवाह) 43. 8 बिलियन अमरीकी डालर थीं, जिसके परिणामस्वरूप 2008-09 के दौरान 2.0 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बहिर्प्रवाह हुआ। इस प्रकार अल्पावधि व्यापार ऋण ने भारत में बड़ी समस्या खड़ी नहीं की। तथापि 2009-10 में स्थिति बदल गई और अल्पावधि व्यापार ऋण अंतर्प्रवाह 27.5 प्रतिशत बढ़कर 53.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया, जबकि अल्पावधि व्यापार ऋण बर्हिप्रवाह मामूली रूप से केवल 4.5 प्रतिशत बढ़कर 45. 7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया जिसके परिणामस्वरूप 7.6 बिलियन अमरीकी डालर का निवल अंतर्प्रवाह हुआ। यह रूझान वित्तीय वर्ष 2010-11में और अधिक मुखर हुआ। 2010-11 की पहली छमाही में भारत के अल्पावधि व्यापार ऋण में 6.7 बिलियन अमरीकी डालर का वृहत निवल अंतर्प्रवाह दर्ज हुआ (2009-10 की पहली छमाही के दौरान 0.05 बिलियन अमरीकी डालर के मामूली निवल बहिर्प्रवाह की तुलना में)। यह सुदृढ़ घरेलू आर्थिक क्रियाकलाप और वैश्विक वित्तीय बाजारों में सुधरी हुई स्थितियों के अनुरूप ही था। 27 मार्च, 2009 को ऋणात्मक वृद्धि के बाद, निर्यात ऋण में 26 मार्च, 2010 को साधारण वृद्धि हुई। निर्यात ऋण वृद्धि में यह रूझान जारी रहा और 31 दिसम्बर 2010 को यह 11.3 प्रतिशत हो गया। तथापि निवल बैंकिंग ऋण के प्रतिशत के रूप में निर्यात ऋण 0.9 प्रतिशतांक गिरकर 28 मार्च, 2008 को 5.5 प्रतिशत से 27 मार्च 2009 को 4.6 प्रतिशत और 31 दिसम्बर, 2010 को 4.1 प्रतिशत हो गया (देखें सारणी 7.2)

7.14 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा व्यापार ऋण व्यवस्था में सुधार लाने, बैंकों द्वारा विदेशी ऋणों पर सीमा में वृद्धि, इक्विजम बैंक को ऋण श्रृंखला तथा विनिमय सुविधा का विस्तार करने हेतु सम्पूर्ण लागत सीमा में वृद्धि से व्यापार वित्त पोषण पर दबाव को कम करने में मदद मिली है। समग्र सकल पूंजी प्रवाहों में अल्पावधि व्यापार ऋण (अंतर्प्रवाह और बहिर्प्रवाह दोनों) के हिस्से में वृद्धि द्वारा इसकी आगे पुष्टि होती है, जहां अंतर्प्रवाहों का हिस्सा 2007-08 में 10.9 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 15.6 प्रतिशत हो गया, वहीं बहिर्प्रवाहों का हिस्सा इसी अवधि के दौरान 9.6 प्रतिशत से बढ़कर 15.8 प्रतिशत हो गया।

सारणी 7.2 : निर्यात क्रेडिट

तिथि को उल्लिखित बकाया	निर्यात क्रेडिट (करोड़ रु. में)	अंतर प्रतिशत	एनबीसी के प्रतिशत के रूप में निर्यात
मार्च 24, 2000	39,118	9.0	9.8
मार्च 23, 2001	43,321	10.7	9.3
मार्च 22, 2002	42,978	-0.8	8.0
मार्च 21, 2003	49,202	14.5	7.4
मार्च 19, 2004	57,687	17.2	7.6
मार्च 18, 2005	69,059	19.7	6.3
मार्च 31, 2006	86,207	24.8	5.7
मार्च 30, 2007	104,926	21.7	5.4
मार्च 28, 2008	129,983	23.9	5.5
मार्च 27, 2009	128,940	-0.8	4.6
मार्च 26, 2010	138,143	7.1	4.3
31 दिसम्बर 2010*	153,794	11.3	4.1

स्रोतः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)

***26 मार्च 2010 को जो आंकड़ा था उससे अंतर-निवल बैंकिंग क्रेडिट**

टिप्पणीः

* मार्च 2004 तक का डाटा चुनिंदा बैंकों से संबंधित है जो 90% बैंक क्रेडिट के लिए उत्तरदायी हैं।

18 मार्च, 2005 से तथा इससे आगे का डाटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को छोड़कर आरबीआई से निर्यात क्रेडिट पुनर्वित्त प्राप्त करने वाले सभी अनुसूचित बैंकों से संबंधित है।

भारत का पण्य बाजार

7.15 वर्ष 2002-03 के बाद भारत की व्यापार वृद्धि 20 प्रतिशत से अधिक पर सुदृढ़ रही है। भारत की व्यापार वृद्धि का जहां विश्व व्यापार वृद्धि के साथ सुदृढ़ सह-संबंध रहा है, यह विशेषकर दो समयावधियों में विश्व व्यापार वृद्धि की अपेक्षा काफी अधिक रही है, पहला 1990 के सुधारों के ठीक बाद और दूसरा 2003 के बाद (देखें चित्र 7.1)

7.16 अनेक अन्य देशों के विपरीत, वैश्विक मंदी ने भारत के निर्यात क्षेत्र में निरन्तर वृद्धि के रूझान पर केवल मामूली रूप से प्रतिकूल प्रभाव डाला। निर्यात में 2008-09 में 13.6 प्रतिशत की अच्छी दर से वृद्धि हुई। 2004-05 से 2008-09 की पांच वर्ष की अवधि के लिए भारत के पण्य निर्यातकी मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) पूर्ववर्ती पांच वर्ष की अवधि के 14 प्रतिशत से बढ़कर 22 प्रतिशत हो गई। तथापि, 2009-10 में निर्यात वृद्धि (-)3.5 प्रतिशत पर ऋणात्मक थी, जो आंशिक रूप से वैश्विक मंदी के प्रभाव और आंशिक रूप से 2008-09 के पिछले बकाया निर्यात आंकड़ों के कारण उच्चतर आधार प्रभाव को दर्शाता है। इस ऋणात्मक वृद्धि के बावजूद, पण्य

चित्र 7.1 विश्व और भारत में निर्यात वृद्धि

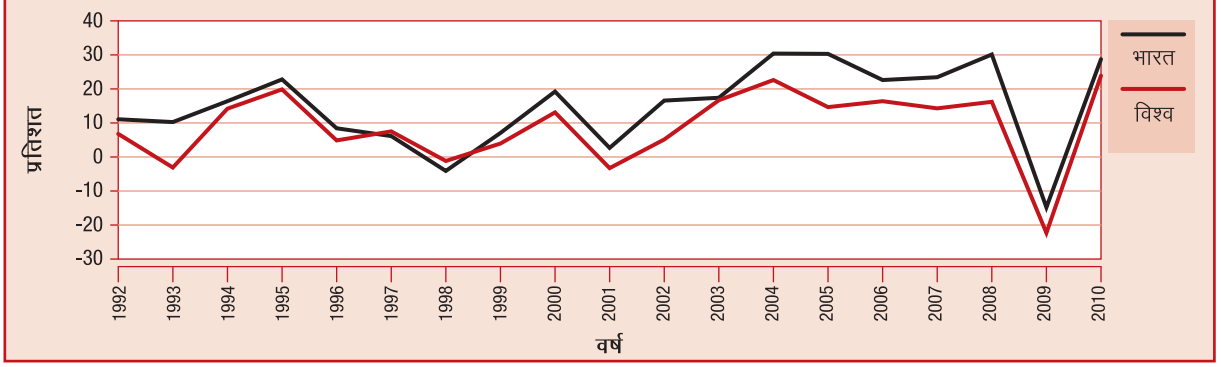

स्रोत : आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ
टिप्पणी : 2010 के आंकड़े केवल तीन तिमाहियों के लिए हैं

व्यापार में प्रमुख निर्यातकों में भारत की रैंकिंग जो 2007 में 26वें से मामूली घट कर 2008 में 27वें स्थान पर पहुंच गई थी, 2009 में सुधर कर 21वीं हो गई है।

7.17 तथापि संपूर्ण वर्ष के लिए अच्छी समग्र तस्वीर उन कुछ कठिनाइयों को छिपा देती है, जो संकट से घिरे 12 महीनों में निर्यात क्षेत्र को झेलनी पड़ी। भारत के मामले में, 2009-10 की दूसरी छमाही से 2010-11 के आरंभ में निर्यात वृद्धि में आमूल-चूल परिवर्तन पहले की गिरावट जैसी ही तीव्र था, जो आंशिक रूप से निम्न आधार और आंशिक रूप से वैश्विक प्रवृत्तियों को दर्शाता है। (देखें चित्र 7.2) निर्यात के क्षेत्र में सरकार द्वारा कुशल संचालन से भी निर्यातकों को इन कठिन महिनों में दिक्कतों को कम करने में मदद मिली।

7.18 यद्यपि फरवरी 2010 से जून 2010 तक उच्च वृद्धि के बाद जुलाई से नवम्बर 2010 तक निर्यात वृद्धि में गिरावट आई, अप्रैल-दिसम्बर 2010-11 में संचयी निर्यात वृद्धि 29.5 प्रतिशत पर अच्छी थी, जबकि इसी अवधि के दौरान संचयी निर्यात 164. 7 बिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गए। वर्तमान संकेत हैं कि भारत न केवल 200 बिलियन अमरीकी डालर के लक्ष्य को प्राप्त करेगा बल्कि 2010-11 में इससे आगे निकल जाएगा।

7.19 वर्ष 2008-09 में डालर की दृष्टि से निर्यात वृद्धि में कमी हुई, जबकि रुपए की दृष्टि से इसके विपरीत बढ़ोत्तरी परिलक्षित हुई जिससे रुपए के 12.5 प्रतिशत तक उच्च मूल्य ह्रास का सीधा प्रभाव देखा गया है। वर्ष 2009-10 में, डालर की दृष्टि से, निर्यात वृद्धि ऋणात्मक थी जबकि रुपए की दृष्टि से 3.1 प्रतिशत तक रुपए का बहुत कम मूल्य ह्रास देखा गया। वर्ष 2010-11(अप्रैल-दिसम्बर) में डालर और रुपया दोनों ही दृष्टि से निर्यात वृद्धि में मजबूती रही, रुपए की दृष्टि से, रुपए का मूल्य 5.0 प्रतिशत बढ़ जाने के कारण, यह वृद्धि थोड़ी कम रही (चित्र 7.3)। इसी अवधि के दौरान, डालर और रुपए की दृष्टि से आयात वृद्धि में घट-बढ़ भी वैसी ही दिखायी दी।

चित्र 7.2 भारत के व्यापार की मासिक प्रवृत्तियां–मूल्य और वृद्धि

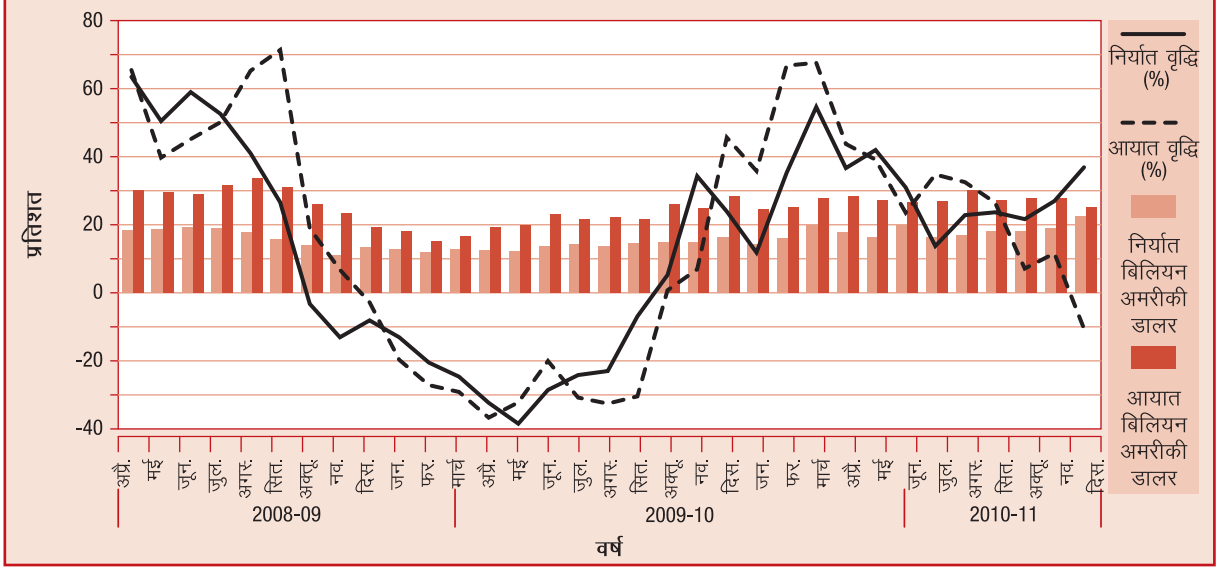

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों पर आधारित

सारणी 7.3 : व्यापार निष्पादन: मात्रा एवं यूनिट मूल्य

(वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन)

	निर्यात				आयात				टर्म आफ ट्रेड	
	मूल्य				मूल्य				निवल	आय
	रुपए में	अमरीकी डालर में	परिमाण	यूनिट मूल्य	रुपए में	अमरीकी डालर	परिमाण	यूनिट मूल्य		
2001-02	2.7	-1.6	0.8	1.0	6.2	1.7	4.0	2.8	-2.1	-1.3
2002-03	22.1	20.3	19.0	2.9	21.2	19.4	5.8	14.3	-9.8	7.4
2003-04	15.0	21.1	7.3	7.5	20.8	27.3	17.4	3.1	3.6	11.2
2004-05	27.9	30.8	11.2	14.9	39.5	42.7	17.2	18.9	-3.5	7.3
2005-06	21.6	23.4	15.1	6.1	31.8	33.8	16.0	14.0	-6.0	8.2
2006-07	25.3	22.6	10.2	13.7	27.3	24.5	9.8	15.1	-1.3	8.8
2007-08	14.7	29.0	7.9	5.1	20.4	35.5	14.1	1.9	2.6	10.7
2008-09	28.2	13.6	9.0	16.9	35.8	20.7	20.2	13.8	2.5	11.7
2009-10	0.6	-3.5	-1.1	1.0	-0.8	-5.0	9.9	-10.0	12.3	11.0
2010-11*	23.4	29.5	-	-	13.6	19.0	-	-	-	-

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, (डीजीसीआईएण्डएस) आंकड़ों से संगणित
अ : अप्रैल-दिसम्बर 2010
निर्यात एवं आयात की मात्रा एवं यूनिट मूल्य सूंचकांक नए आधार (1999-2000=100) के साथ हैं।

7.20 वर्ष 2009-10 में रुपए की दृष्टि से निर्यात वृद्धि में आई गिरावट न सिर्फ 2008-09 में 16.9 प्रतिशत की तुलना में 1.0 प्रतिशत की यूनिट मूल्य में वृद्धि की बड़ी गिरावट के कारण था, बल्कि 2008-09 में 9 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 1.1 प्रतिशत की मात्रा में वास्तविक गिरावट के कारण थी। यह मुख्य रूप से विनिर्मित वस्तुओं की मात्रा और यूनिट मूल्य दोनों में ऋणात्मक

चित्र 7.3 निर्यात वृद्धि और विनिमय दर घट-बढ़

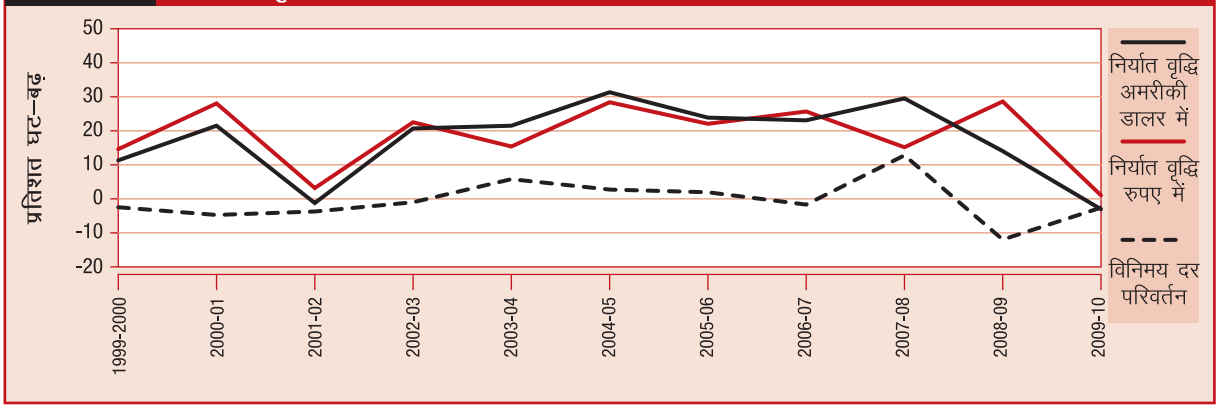

चित्र 7.4 आयात वृद्धि और विनिमय दर घट-बढ़

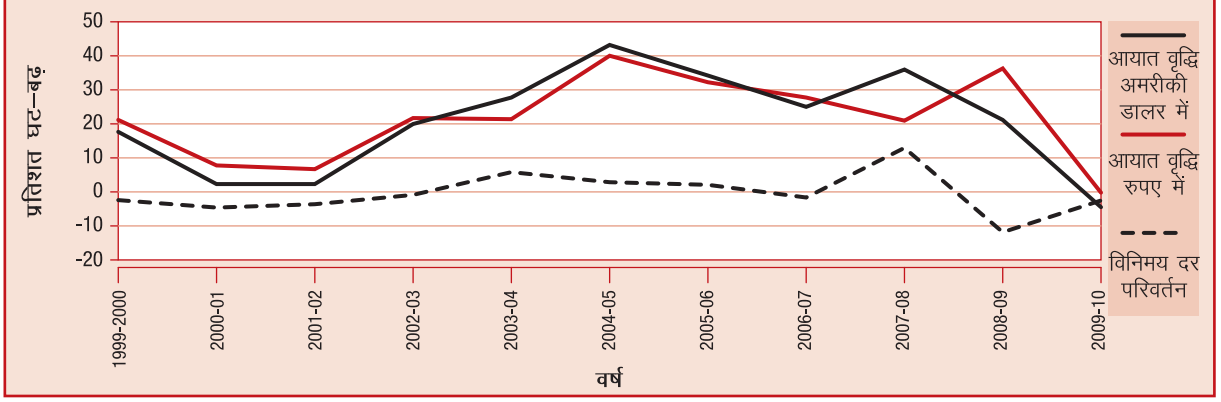

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस और आरबीआई पर आधारित

वृद्धि के कारण था। खाद्य और खाद्य पदार्थों जैसे चावल, कॉफी, मसाले और खली की निर्यात मात्रा भी घट गई (यद्यपि उनके यूनिट मूल्यों में वृद्धि हुई)। यह मुख्य रूप से आपूर्ति की बाधाओं और गैर-बासमती चावल के मामले में निर्यात पर प्रतिबंध जैसे नीतिगत उपायों के कारण था।

7.21 निर्यात मात्रा सूचकांकों का क्षेत्रवार विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि दशक में पहली बार ऋणात्मक मात्रा वृद्धि लगभग सभी क्षेत्रों के लिए, केवल दक्षिण अफ्रीकी विकास समुदाय, एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग और यूरोपीय संघ को छोड़कर ऋणात्मक मात्रा वृद्धि के कारण था। विशेषतया, दक्षिण पूर्व एशियाई संगठन के देशों (अशियान)हेतु (-)8.0 प्रतिशत की वृद्धि और उत्तरी अमरीका हेतु (-)5.8 प्रतिशत जो हमारे प्रमुख व्यापार साझीदारों में हैं और राष्ट्रमंडल स्वतंत्र राज्यों (सीआईएस) के लिए -22.0 प्रतिशत की उच्च ऋणात्मक वृद्धि है, ने निर्यात की मात्रा में इसके गिरावट में योगदान दिया। इसी प्रकार, आयात यूनिट मूल्य सूचकांकों का क्षेत्रवार विश्लेषण यह प्रदर्शित करता है कि दशक में पहली बार ऋणात्मक वृद्धि, दक्षिण अफ्रीकी विकास सामुदायिक के अपवाद होने के चलते सभी क्षेत्रों से आयात में यूनिट मूल्यों में हुई ऋणात्मक वृद्धि के कारण था।

7.22 रुपए की दृष्टि से 2009-10 में आयात की गिरावट रही जो कि यूनिट मूल्य सूचकांकों के उच्च ऋणात्मक वृद्धि के कारण थी जबकि इस दौरान मात्रात्मक वृद्धि सामान्य रूप से उच्च बना हुआ था। यह बदले में साधारण मात्रा वृद्धि, मशीनरी और परिवहन उपकरण के ऋणात्मक यूनिट मूल्य वृद्धि, निम्न मात्रा वृद्धि, विविध विनिर्माण वस्तुओं में ऋणात्मक इकाई मूल्य वृद्धि और खनिज ईंधन और गैर-ईंधन कच्ची सामग्रियों, उनके धनात्मक मात्रा वृद्धि के बावजूद रसायनों और संबद्ध उत्पादों में उच्च ऋणात्मक इकाई मूल्य के कारण था।

7.23 व्यापार के निवल संदर्भ, जो आयात के यूनिट मूल्य सूचकांक के अनुपात के रूप में निर्यात के यूनिट मूल्य सूचकांक को मापता है, आयात के यूनिट मूल्य सूचकांक के वृद्धि के रूप में निर्यात के यूनिट मूल्य सूचकांक में अति सीमांत धनात्मक वृद्धि के बावजूद 12.3 प्रतिशत तक की सुधार देखा गई। इसके अलावा निर्यातों की यूनिट मूल्य सूची में बहुत थोड़ी वृद्धि की तुलना में आयातों की यूनिट मूल्य सूची वृद्धि दस वर्षों में पहली बार ऋणात्मक रही और यह कमी 10 प्रतिशत की उच्च दर पर थी। आयात की क्षमता दर्शाने वाले व्यापार के आय की दृष्टि से विगत दो वर्षों में 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। लेकिन, विगत दो वर्षों के विपरीत यह व्यापार के शुद्ध वस्तु-विनिमय की दृष्टि से उच्च वृद्धि के कारण था जबकि इसी दशक में पहली बार निर्यात मात्रा वृद्धि ऋणात्मक थी।

7.24 विश्व पण्य निर्यात में भारत का हिस्सा 2007 में 0.1 प्रतिशत की बहुत धीमी दर से बढ़ना प्रारंभ हुआ था जो कि 2009 में 1.3 प्रतिशत और 2010 में (जनवरी-जून) 1.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। यह मुख्यतया भारत की अपेक्षा विश्व निर्यात वृद्धि में सापेक्षतया धीमी वृद्धि अथवा तेज गिरावट के कारण था। (सारणी 7.4)। 5.8 प्रतिशत बिन्दु पर 2000 और 2009 के बीच विश्व निर्यात में चीन के हिस्से में वृद्धि इस अवधि में उभरते और विकासशील देशों के हिस्से में कुल वृद्धि का 50 प्रतिशत है जबकि 0.7 प्रतिशत बिन्दु के हिस्से में भारत की वृद्धि कुल वृद्धि

सारणी 7.4 निर्यात वृद्धि और विश्व निर्यात में हिस्सेदारी: भारत एवं अन्य देश

परिवर्तन	मूल्य (अमरीकी डालर बिलियन 2009	विकास दर % सीएजीआर 2000-07	2008	2009	2010 (जनवरी-जून)	विश्व निर्यात में हिस्सा (%) वार्षिक 2000	2008	2009	2010 (जनवरी-जून)	भागीदारी में 2009/2000
चीन	1202	25.4	17.3	-15.9	35.1	3.9	8.9	9.7	10.0	5.8
कोरिया	362	11.6	13.6	-14.3	34.3	2.7	2.6	2.9	3.1	0.2
हांगकांग	319	7.9	5.3	-12.2	24.8	3.2	2.3	2.6	2.6	-0.6
रूस	303	18.9	33.1	-35.7	51.4	1.7	3.0	2.5	2.7	0.8
सिंगापुर	270	11.7	13.0	-20.2	37.4	2.2	2.1	2.2	2.3	0.0
मेक्सिको	230	7.3	7.3	-21.3	35.4	2.6	1.8	1.9	2.0	-0.8
ताईवान	204	7.6	3.5	-20.1	49.3	2.3	1.6	1.6	1.9	-0.7
मलेशिया	165	19.8	29.7	-15.2	35.3	0.7	1.2	1.3	1.4	0.7
ब्राजील	157	8.7	19.1	-24.9	36.9	1.5	1.3	1.3	1.4	-0.3
थाईलैंड	153	16.5	23.2	-22.7	27.5	0.9	1.2	1.2	1.3	0.4
इंडोनेशिया	152	12.1	12.9	-12.0	36.8	1.1	1.1	1.2	1.3	0.1
दक्षिण अफ्रीका	119	8.8	18.3	-14.4	38.1	1.0	0.9	1.0	1.0	-0.1
उभरती तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाएं	63	12.8	21.3	-26.0	31.2	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0
	4572	16.9	25.3	-24.4	26.7	25.4	37.9	37.0	37.4	11.6
विश्व	**12,358**	**11.7**	**15.9**	**-22.7**	**24.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**-**

स्रोत : अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, आईएमएफ नवम्बर, 2010 से परिकलित
टिप्पणी : ईडीई का तात्पर्य उभरते हुए और विकासशील देश है।

का सिर्फ 6 प्रतिशत बनता है। तथापि, चीन की निर्यात वृद्धि पर, जो इस दशक में 2007 तक 25 प्रतिशत से ऊपर थी 2008 में 17.3 प्रतिशत पर आ गई तथा वैश्विक मंदी के फलस्वरूप 2009 में ऋणात्मक (-) 15.9 प्रतिशत हो गई। इसमें वसूली और निम्न आधार प्रभाव के परिणामस्वरूप सामान्य प्रवृत्ति का अनुपालन करते हुए 2010 की पहली छमाही में 35.1 प्रतिशत का सुधार हुआ। भारत की आयात वृद्धि 2009 में -15.2 प्रतिशत पर भी ऋणात्मक रही लेकिन 2010 (जनवरी-जून) में 35.5 प्रतिशत का सुधार हुआ। चूंकि 2010 की पहली छमाही में रूस की निर्यात वृद्धि 51.4 प्रतिशत पर काफी उच्च है जो 2009 में -35. 7 प्रतिशत था। विश्व निर्यात में इसकी गिरावट रूस के हिस्से के बराबर रही जो गिरकर 3.0 से 2.5 प्रतिशत हो गई थी।

7.25 एशिया में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार क्रियाकलाप, जो 2010 में पहली दो तिमाहियों में पर्याप्त तौर पर उछाल रहा, तीसरी तिमाही में धीमी रही। यह आंशिक रूप से आधार प्रभाव के फलस्वरूप हैं और 2010 के तीसरी तिमाही में व्यापार में वैश्विक प्रवृत्ति के आंशिक प्रतिबिंबित रहा। निर्यात और आयात दोनों ने हांगकांग और फिलीपींस को छोड़कर अधिकांश उभरते एशियाई देशों के लिए तीसरी तिमाही में आई गिरावट के साथ लगभग इसी प्रकार की वृद्धि का प्रदर्शन किया। वहीं विगत दो तिमाहियों की तुलना में निर्यात में वृद्धि में मामूली सुधार हुआ।

7.26 भारत का पण्य आयात भी वैश्विक मंदी से प्रभावित हुआ वर्ष 2009-10 में -5.0 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के साथ 288.4 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। यह पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) के आयात में 7.0 प्रतिशत तथा गैर-पीओएल में 4.2 प्रतिशत की वृद्धि में गिरावट के कारण था।

सारणी 7.5 : वर्ष 2010 में प्रमुख एशियाई अर्थव्यवस्था के त्रैमासिक व्यापार वृद्धि

देश		वर्षा-न-वर्ष वृद्धि (%)		
		Q1	Q2	Q3
चीन	निर्यात	28.7	40.9	32.3
	आयात	64.8	43.6	27.1
	कुल व्यापार	**44.1**	**42.2**	**29.8**
हांगकांग	निर्यात	25.8	23.9	27.4
	आयात	34.2	29.4	23.8
	कुल व्यापार	**30.1**	**26.7**	**25.5**
भारत	निर्यात	36.4	30.1	19.6
	आयात	61.6	32.3	31.0
	कुल व्यापार	**50.8**	**31.5**	**26.5**
इंडोनेशिया	निर्यात	44.7	32.5	24.2
	आयात	49.9	44.7	29.6
	कुल व्यापार	**47.0**	**37.8**	**26.6**
दक्षिण कोरिया	निर्यात	35.8	33.1	23.7
	आयात	37.4	43.0	24.5
	कुल व्यापार	**36.6**	**37.5**	**24.1**
मलेशिया	निर्यात	40.8	33.2	23.1
	आयात	45.4	42.7	29.9
	कुल व्यापार	**42.7**	**37.4**	**26.1**
फिलिपींस	निर्यात	42.9	33.3	39.9
	आयात	33.3	25.4	21.3
	कुल व्यापार	**37.5**	**28.9**	**29.9**
सिंगापुर	निर्यात	38.3	36.6	27.5
	आयात	35.3	33.8	22.6
	कुल व्यापार	**36.9**	**35.3**	**25.2**
थाईलैंड	निर्यात	31.6	41.5	21.9
	आयात	58.1	46.0	30.5
	कुल व्यापार	**43.4**	**43.6**	**25.9**

स्रोत: डब्ल्यू टी ओ डाटा से परिकलित
टिप्पणी: वर्षा-नु-वर्ष

चित्र 7.5 पी.ओ.एल. आयात

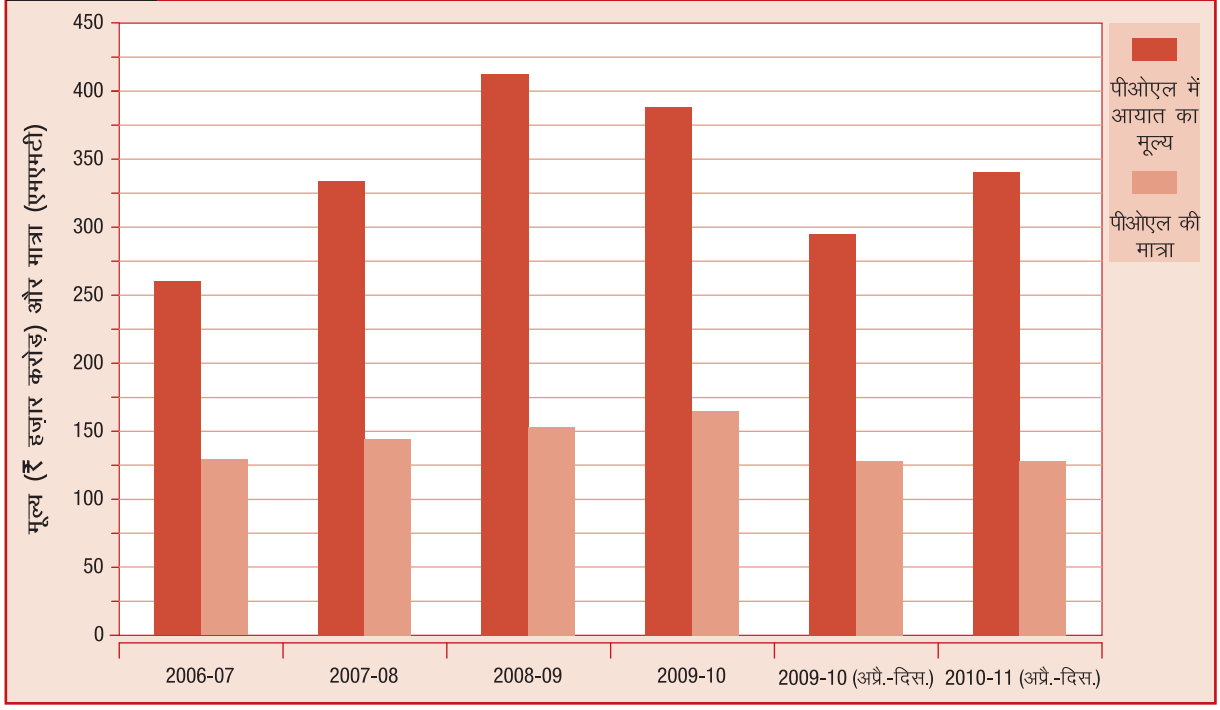

स्रोत: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

चित्र 7.6 कच्चे तेल की कीमत (अमरीकी डालर/बैरल)

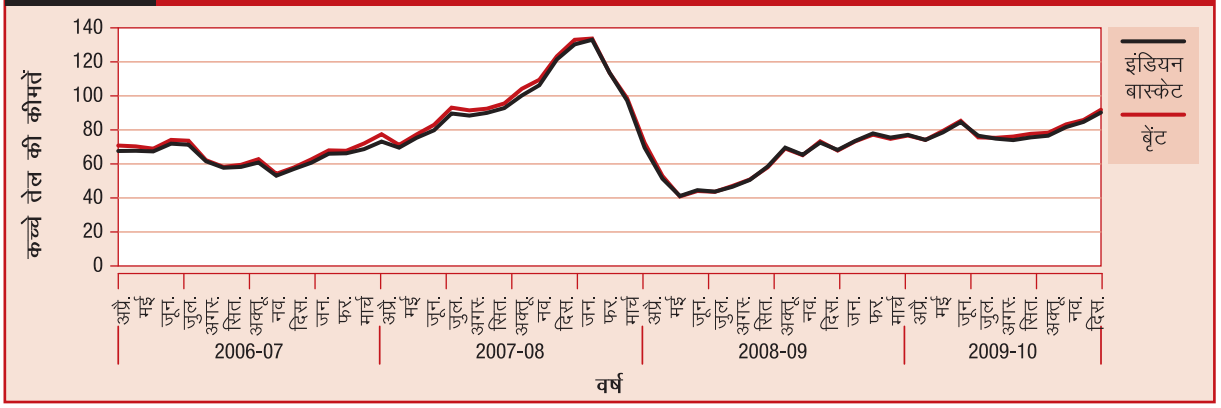

स्रोत : पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आंकड़ों पर आधारित

7.7 प्रतिशत की मात्रा में बढ़ोतरी के बावजूद पीओएल आयात वृद्धि मुख्यत: 16.5 प्रतिशत की भारतीय अपरिष्कृत तेल आयात बास्केट के आयात मूल्यों में गिरावट के कारण था। (चित्र 7.5)

7.27 तेल की अन्तरराष्ट्रीय कीमतों में 2008 के दौरान अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई तथा समूची आगामी अवधि के दौरान यह काफी अस्थिर बनी रही। कच्चे तेल के भारतीय बास्केट की कीमत जो तेल की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप चलती रही, भी अस्थिर थी। यह वैश्विक मंदी के बाद तेजी से गिरने के पूर्व 3 जुलाई, 2008 को 142 अमरीकी डालर प्रति बैरल पर पहुंचने के बाद 2008-09 के दौरान औसतन 83.57 अमरीकी डालर प्रति बैरल रही। 2006-07 से 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) तक तेल की कीमतों में मासिक घट-बढ़ स्पष्ट रूप से इस आस्थिरता को परिलक्षित करता है। वर्तमान तेल की कीमतें लगभग 95-100 अमरीकी डालर प्रति बैरल हैं जिसमें ब्रेंट कच्चे तेल के मूल्य फरवरी 2011 में 100 अमरीकी डालर के मार्क को पार कर गया और भारतीय कच्चा तेल बेसेट 11 फरवरी 2011 को 98.4 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गया।

7.28 2009-10 में पीओएल भिन्न और सर्राफा भिन्न आयातों में 8.6 प्रतिशत की गिरावट आई जो औद्योगिक क्रियाकलाप के लिए आयातों हेतु कम मांग को परिलक्षित करता है। यह आंशिक रूप से निम्न औद्योगिक वृद्धि और निर्यात में गिरावट के कारण है जिसके परिणामस्वरूप निर्यात के लिए आवश्यक निविष्टियों के आयात की कम मांग हुई। आयात में भी 2009-10 की दूसरी छमाही में तेजी आनी आरंभ हुई, हालांकि यह एक माह पिछड़ने के बाद शुरू हुई जिससे दिसम्बर, 2009 में नौ महीने की निरन्तर ऋणात्मक वृद्धि का अंत हुआ। आयात की स्थिति में आमूलचूल परिवर्तन कहीं अधिक तीव्र था जिसमें आयात की वृद्धि फरवरी और मार्च, 2010 में 73.5 और 78.3 प्रतिशत थी। यह आंशिक रूप से आधार प्रभाव और आंशिक रूप से निर्यात और औद्योगिक गतिविधि में तेजी के कारण था। 2010-11 के दौरान (अप्रैल-दिसम्बर) आयात वृद्धि 19 प्रतिशत थी जिसके साथ पीओएल और पीओएल-भिन्न दोनों आयातों में वृद्धि क्रमश: 17. 7 प्रतिशत और 19.6 प्रतिशत थी। सोने और चांदी के आयात में 8.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। औद्योगिक क्रियाकलाप और निर्यात में सुधार के कारण पीओएल-भिन्न, सर्राफा-भिन्न आयातों में 21.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

7.29 व्यापार घाटा (सीमा शुल्क आधार) 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) में 2.4 प्रतिशत बढ़कर 82 बिलियन अमरीकी

सारणी 7.6 : पीओएल व्यापार एवं गैर-पीओएल आयात में वृद्धि (अमरीकी डालर में)

	कुल आयात	पीओएल आयात	पीओएल निर्यात	निवल पीओएल आयात	गैर-पीओएल आयात	सोना एवं चांदी आयात	गैर-पीओएल गैर-सोना एवं चांदी आयात
2001-02	1.7	-10.5	13.3	-13.8	7.2	-1.2	8.5
2002-03	19.4	26.0	21.6	26.8	17.0	-6.4	20.3
2003-04	27.3	16.6	38.5	12.9	31.5	59.9	28.5
2004-05	42.7	45.1	95.9	34.4	41.8	62.6	39.0
2005-06	33.8	47.3	66.5	41.4	28.8	1.5	33.1
2006-07	24.5	29.8	60.1	18.9	22.3	29.5	21.4
2007-08	35.5	39.8	52.5	33.7	33.6	21.0	35.2
2008-09	20.7	17.4	-3.0	28.7	22.2	26.4	21.7
2009-10	-5.0	-7.0	2.3	-10.9	-4.2	32.8	-8.6
2010-11(अप्रैल-सित.)	26.0	29.7	66.0	15.1	24.5	12.1	26.3

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस तथा अपनी स्वयं की गणनाएं

डालर हो गया जबकि पूर्व वर्ष की इसी अवधि में यह 80.1 बिलियन था। व्यापार घाटा 2008-09 में 118.4 बिलियन अमरीकी डालर के उच्चतम स्तर पर था और 2009-10 में इसमें कुछ सुधार होकर यह 109.6 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। 2010-11 की पहली छमाही में निर्यात वृद्धि की तुलना में अपेक्षाकृत उच्चतर आयात वृद्धि ने व्यापार घाटों के कारण एक संभावित अनियंत्रणीय चालू खाता घाटे का खतरा उत्पन्न किया। अक्तूबर, 2010 से आयात वृद्धि के धीमा पड़ने और नवम्बर, 2010 में निर्यात में तेजी आने से, यह डर कि उच्च चालू खाता घाटा उच्च पण्य व्यापार घाटे के कारण हो सकता है, अब समाप्त हो रहा है। निवल पीओएल आयात वृद्धि, जो 2002-03 से सकारात्मक रही है, सात वर्षों के अंतराल के बाद 2009-10 में -10.9 प्रतिशत पर ऋणात्मक रही है। तथापि, 2010-11 के दौरान (अप्रैल-सितम्बर) यह 15.1 प्रतिशत की वृद्धि के साथ पुन: सकारात्मक हो गई है। (सारणी 7.6)

व्यापार संरचना

निर्यात संरचना

7.30 निर्यात बॉस्केट में इस दशक में बड़े संरचनात्मक परिवर्तन देखे गए हैं जिसमें विनिर्माण के हिस्से में 10 प्रतिशतांक की गिरावट कच्चे पेट्रोलियम और उत्पादों के हिस्से में 12.6 प्रतिशतांक का लाभ और प्राथमिक उत्पादों के हिस्से में 3.3 प्रतिशतांक की गिरावट दर्ज हुई। यह रूझान गत दो वर्षों अर्थात् 2008-09 से 2010-11 की पहली छमाही के दौरान जारी रहा है, अर्थात् विनिर्माण 68.9 प्रतिशत पर अवरुद्ध रहा और यहां तक कि 2009-10 में इसमें गिरावट आई; प्राथमिक उत्पादों का हिस्सा 2009-10 में बढ़ने के बाद 2010-11 की पहली छमाही में 12. 7 प्रतिशत तक गिर गया; और कच्चे पेट्रोलियम और उत्पादों का हिस्सा 2009-10 और 2010-11 की पहली छमाही दोनों में लगातार बढ़कर 16.9 प्रतिशत हो गया। विनिर्माण के भीतर पिछले दो वर्षों में कोई बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है। तथापि 2000-01 की तुलना में, इंजीनियरिंग वस्तुओं का हिस्सा बहुत अधिक बढ़ गया है जबकि रेडीमेड वस्त्रों सहित टेक्सटाइल का हिस्सा बहुत अधिक गिरकर 2000-01 में 23.6 प्रतिशत से 2010-11 की पहली छमाही में 9.5 प्रतिशत हो गया। रसायनों और संबद्ध उत्पादों के हिस्से में कुछ बढ़ोत्तरी हुई है, जबकि चमड़ा और चर्म विनिर्मित उत्पादों और हस्तशिल्प के हिस्से में कमी आई है।

7.31 2008-09 की तुलना में 2010-11 की पहली छमाही में प्रमुख गंतव्य देशों को भारत के प्रमुख निर्यातों की वस्तु-वार वृद्धि की तुलना संयुक्त राज्य अमरीका और यूरोपीय संघ को विनिर्माण वस्तुओं के निर्यात के हिस्से में गिरावट दर्शाता है जबकि 'अन्य' के मामले में वृद्धि हुई है। पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पादों के मामले में, सभी तीन गंतव्य स्थलों को निर्यात के हिस्से में वृद्धि हुई है जिसमें यूरोपीय संघ बाजार को निर्यात में अधिक वृद्धि हुई है। इसमें यूरोपीय संघ और अमरीकी बाजारों को 2009-10 और 2010-11 की पहली छमाही में निर्यात में अधिक वृद्धि हुई है। प्राथमिक उत्पादों के मामले में, एकमात्र बड़ा परिवर्तन 'अन्य' के हिस्से में गिरावट था। (देखें सारणी 7.7)

7.32 यूरोपीय संघ को भारत के विनिर्माण निर्यात में जहां 2009-10 में उच्च ऋणात्मक वृद्धि का सामना करना पड़ा, वहीं 2010-11 की पहली छमाही में सुधार अन्य दो गंतव्यों को विनिर्माण निर्यातों के सुदृढ़ सुधार की तुलना में साधारण था। विनिर्माण वस्तुओं में, विभिन्न उत्पाद समूहों के निष्पादन में भिन्नता थी। संयुक्त राज्य और यूरोपीय संघ को टेक्सटाइल के निर्यात के मामले में, इसके हिस्से में गिरावट देखी गई। यूरोपीय संघ के मामले में यह गिरावट कहीं अधिक थी। यूरोपीय संघ को ऋणात्मक निर्यात वृद्धि 2010-11 की पहली छमाही में भी जारी रही, जबकि तीन लगातार वर्षों की ऋणात्मक वृद्धि के बाद संयुक्त राज्य को निर्यात वृद्धि में साधारण तेजी आई। रत्न और आभूषणों में भी, 2008-09 की तुलना में 2010-11 की पहली छमाही में, यूएस और यूरोपीय संघ दोनों को निर्यात का हिस्से में कमी आई। यूएस और ईयू को इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के मामले में थी, हिस्से में गिरावट आई जिसमें ईयू के मामले में गिरावट अपेक्षाकृत अधिक था। दूसरी तरफ, 'अन्य को निर्यात के हिस्से में, 50 प्रतिशत की उच्च वृद्धि के साथ बढ़ोत्तरी हुई (देखें बॉक्स 7.2)। रसायनों और संबंधित उत्पादों के मामले में, यूएस को निर्यातों के हिस्से लगभग प्रतिशतांक की वृद्धि हुई, जबकि यूरोपीय संघ के मामले में यह स्थिर था और 'अन्य' के मामले में मामूली गिरा। यूरोपीय संघ, जहां वैश्विक मंदी से उबरने की स्थिति कमजोर है, को भारत के निर्यात में मंदी एक चिन्ता का विषय है।

आयात संरचना

7.33 इस दशक में आयातों की संरचना में भी परिवर्तन हुआ। खाद्य और सम्बद्ध उत्पादों के आयात का हिस्सा, जो 2000-01 में 3.3 प्रतिशत से गिर कर 2008-09 में 2.1 प्रतिशत रह गया था, 2009-10 में बढ़ कर 3.7 प्रतिशत तथा 2010-11 की पहली छमाही में गिरकर 3.2 प्रतिशत रह गया, जिसमें खाद्य तेलों और दालों के आयात के हिस्से में मामूली गिरावट आई (सारणी 7.8)। तथापि ईंधन आयात का हिस्सा लगभग 33 प्रतिशत बना रहा। सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन पूंजीगत वस्तुओं के हिस्से में एकाएक बढ़ोत्तरी थी जो 2000-01 में 10.5 प्रतिशत से 2009-10 में 15.0 प्रतिशत हो गया और परिवहन उपस्कर के आयात के हिस्से और वृद्धि दर में घट-बढ़ के कारण 2010-11 की पहली छमाही में फिर गिरकर 13.1 प्रतिशत हो गया। आयात बास्केट में सोने और चांदी तथा इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं का हिस्सा 2008-09 और 2009-10 की तुलना में 2010 की पहली छमाही में कम हो गया। मोती, कीमती और कम कीमती रत्नों के हिस्से में अत्यधिक घट-बढ़ होती रही जिसमें 2009-10 में ऋणात्मक वृद्धि और

वॉक्स 7.2 : भारतीय इंजीनियरिंग सेक्टर: अधिक ध्यान देने की आवश्यकता

इंजीनियरिंग उद्योग भारतीय औद्योगिक सेक्टर का सबसे बड़ा भाग है। इसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत हिस्सा है और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 30.5 प्रतिशत भारांश है; कुल निवेश में इसका हिस्सा 29.9 प्रतिशत है; और विदेशी साझेदारियों में 62.8 प्रतिशत हिस्सा है। इंजीनियरिंग निर्यात देश के लिए सबसे बड़े विदेशी मुद्रा अर्जकों में एक है और भारत के कुल निर्यात का यह 20 प्रतिशत से अधिक बनता है। इंजीनियरिंग निर्यात का लगभग 35 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सेक्टर से आता है।

2000-01 से 2007-08 के दौरान भारत की इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात 25.2 प्रतिशत पर बढ़ा। 2008-09 में, यह वृद्धि घटकर 18.7 प्रतिशत रह गई और 2009-10 में वैश्विक मंदी के कारण यह गिर कर 19.6 प्रतिशत रह गई और कुल निर्यात में इसका हिस्सा घटकर 18.2 प्रतिशत रह गया। 2010-11 की पहली छमाही में, आंशिक रूप से आधार प्रभाव के कारण और आंशिक रूप से प्रोत्साहन उपायों के बाद वैश्विक पुनरोत्थान के कारण 46.0 प्रतिशत की सुदृढ़ वृद्धि हुई ।

इंजीनियरिंग मदों के निर्यात के प्रमुख श्रेणियों का निष्पादन यह दर्शाता है कि 2009-10 में, इंजीनियरिंग वस्तुओं की प्रमुख श्रेणियों में ऋणात्मक वृद्धि रही है। 2010-11 की पहली छमाही में, सभी प्रमुख श्रेणियों जैसे मशीनरी, लौह और इस्पात और अन्य इंजीनियरिंग वस्तुओं में उच्च वृद्धि दर्ज हुई जिसमें प्रमुख उप-श्रेणियों जैसे परिवहन उपस्कर, प्राथमिक और सेमिफिनिश्ड लौह और इस्पात, गैर-अयस्क धातुएं और धातुओं की विनिर्मित वस्तुओं में क्रमश: 61.8 प्रतिशत, 65.0 प्रतिशत, 61.5 प्रतिशत और 40.3 प्रतिशत की अत्यधिक वृद्धि दर्ज हुई। केवल एक प्रमुख उप-श्रेणी अर्थात मशीनरी और औजार में 10.5 प्रतिशत की साधारण वृद्धि दर्ज हुई (देखें सारणी 1)

सारणी 1 : विभिन्न इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात निष्पादन

इंजीनियरिंग श्रेणियां	भारत के कुल निर्यात में हिस्सा(%)				वृद्धि दर (%)	
	2008-09	2009-10	2009-10 (अप्रै.-सित.)	2010-11 (अप्रै. सित.)	2009-10	2010-11 (अप्रै. सित.)
1) मशीनरी	12.2	11.0	12.5	13.3	-13.3	37.7
(क) मशीन टूल्स	0.2	0.2	0.2	0.1	-26.4	-1.2
(ख) मशीनरी और औजार	5.9	5.3	5.7	4.8	-13.3	10.5
(ग) परिवहन उपस्कर	6.1	5.5	6.7	8.3	-12.9	61.8
2) लौह और इस्पात	3.2	2.0	1.9	2.3	-39.2	63.9
(क) लौह और इस्पात बार रॉड आदि	0.6	0.4	0.4	0.4	-34.2	59.1
(ख) प्राथमिक और अर्द्ध-निर्मित लौह और इस्पात	2.6	1.6	1.5	1.9	-40.4	65.0
3) अन्य इंजीनियरिंग मदें	6.4	5.2	5.1	6.2	-21.7	59.8
(क) फेरो-मिश्र धातुएं	0.8	0.5	0.4	1.0	-43.1	229.4
(ख) उत्पादों के अतिरिक्त एलुमिनियम उत्पाद	0.3	0.3	0.3	0.3	11.3	63.5
(ग) गैर अयस्क धातुएं	1.1	1.2	1.0	1.3	5.4	61.5
(घ) धातुओं की विनिर्मित वस्तुएं	4.1	3.1	3.3	3.6	-27.2	40.3
(ड़) अवशिष्ट इंजीनियरिंग मदें	0.1	0.1	0.1	0.1	-5.9	37.6
जोड़ इंजीनियरिंग निर्यात	21.8	18.2	19.5	21.8	-19.6	46.0

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस

भारतीय इंजीनियरिंग निर्यातों के लिए प्रमुख बाजार है-संयुक्त राज्य अमरीका, सिंगापुर, यूएई, यूके, चीन, जर्मनी और इटली। यह उल्लेखनीय है कि जबकि 2009-10 में अधिकांश बाजारों को भारत के इंजीनियरिंग निर्यातों की वृद्धि में गिरावट आई, वहीं चीन को इसका इंजीनियरिंग निर्यात 62 प्रतिशत से अधिक बढ़ा।

2008 में विश्व इंजीनियरिंग निर्यात के 0.8 प्रतिशत हिस्से के साथ, भारत का वैश्विक इंजीनियरिंग निर्यात बाजार में-सभी तुलनात्मक देशों से नीचे-30वां स्थान है। इस निम्न स्थिति के मुख्य रूप से तीन कारण हैं: 1) निम्न निर्यात सघउ अनुपात: भारत का निर्यात से सघउ का 15 प्रतिशत का अनुपात जो अन्य तुलनीय देशों में 27 प्रतिशत है। 2) निम्न इंजीनियरिंग से निर्यात का अनुपात-भारत का कुल निर्यात में इंजीनियरिंग निर्यात का अनुपात 24 प्रतिशत है जबकि अन्य तुलनीय देशों में यह 30 प्रतिशत है। 3) इंजीनियरिंग निर्यातों की निम्न प्रौद्योगिकी उत्पादों का हिस्सा 62 प्रतिशत है जो अन्य तुलनीय देशों में 71 प्रतिशत है। विश्व इंजीनियरिंग निर्यात में भारत के वर्तमान कम हिस्से और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार की बहुत अधिक गुंजाइश को देखते हुए, विश्व व्यापार के इस प्रमुख सेक्टर में उच्चतर वृद्धि हासिल करने की संभावना है।

सारणी 7.7 : प्रमुख बाजारों के अनुसार निर्यात की संरचना

	प्रतिशत हिस्सा					सीएजीआर	वृद्धि दर[क]			
	2000-01	2008-09	2009-10	2009-10 (अप्रैल-सित.)	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2000-01 to 2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 (अप्रैल-सित.)	2010-11 (अप्रैल-सित.)
I. प्राथमिक उत्पाद										
विश्व	16.0	13.9	14.9	13.4	12.7	19.7	1.7	3.8	-27.8	23.2
अमरीका	9.4	7.2	6.8	7.0	7.7	7.9	2.9	-13.5	-27.4	42.6
ई.यू.	13.1	8.4	8.6	9.0	8.5	12.7	1.7	-5.7	-23.5	15.8
अन्य	19.8	16.7	18.0	15.7	14.5	22.8	1.6	6.6	-28.5	23.0
(क) कृषि एवं संबद्ध उत्पाद										
विश्व	14.0	9.6	10.0	9.3	8.5	14.6	9.7	1.1	-28.4	18.7
अमरीका	9.0	6.0	5.8	5.9	6.6	4.4	13.1	-12.1	-25.9	45.1
ईयू	11.9	6.9	7.1	7.4	7.1	10.6	6.6	-6.4	-23.5	17.1
अन्य	16.8	11.0	11.6	10.4	9.1	17.1	10.0	3.8	-29.5	16.6
(ख) अयस्क एवं खनिज										
विश्व	2.0	4.3	4.9	4.1	4.2	38.9	-12.5	9.9	-26.5	33.5
अमरीका	0.4	1.2	1.0	1.1	1.1	37.9	-29.6	-21.1	-34.5	29.8
ईयू	1.3	1.4	1.5	1.6	1.4	26.0	-16.7	-2.5	-23.3	9.5
अन्य	3.0	5.7	6.5	5.3	5.4	40.7	-11.4	11.9	-26.5	35.7
II विनिर्मित वस्तुएं										
विश्व	78.8	68.9	67.2	71.1	68.9	16.7	23.1	-5.9	-21.4	26.1
अमरीका	90.6	90.2	89.1	88.5	88.7	11.3	7.1	-8.7	-24.9	30.4
ईयू	86.8	79.3	73.2	77.3	73.5	15.8	20.6	-15.4	-29.5	15.7
अन्य	70.9	62.0	62.0	66.5	64.5	19.3	28.9	-1.3	-17.3	28.7
(क) आरएमजी सहित कपड़ा										
विश्व	23.6	10.2	10.5	11.3	9.5	8.1	4.4	-1.2	-8.4	9.7
अमरीका	27.2	18.4	18.4	19.1	16.9	7.1	-4.8	-7.6	-14.1	15.1
ईयू	29.2	18.2	18.5	19.9	15.7	11.4	7.9	-6.7	-10.5	-4.1
अन्य	19.8	6.4	6.9	7.5	6.7	6.3	6.2	6.9	-3.9	18.1
(ख) रत्न एवं आभूषण										
विश्व	16.6	15.1	16.2	17.0	14.9	15.0	42.1	3.7	-20.9	14.2
अमरीका	29.3	21.7	24.2	24.2	20.3	8.9	-7.7	2.8	-23.3	8.9
ईयू	11.5	8.3	6.7	6.9	6.4	11.3	24.8	-26.2	-48.5	12.8
अन्य	13.9	16.1	17.8	18.7	16.3	19.8	66.2	8.8	-15.5	15.4
(ग) इंजीनियरिंग वस्तुएं										
विश्व	15.7	21.8	18.2	19.5	21.8	25.2	18.7	-19.6	-32.1	46.0
अमरीका	13.4	23.9	17.1	16.4	22.2	19.5	16.1	-33.9	-48.7	75.8
ईयू	14.0	25.4	20.8	22.2	22.1	27.1	25.7	-25.1	-41.0	21.1
अन्य	17.2	20.0	17.6	19.2	21.7	26.0	16.6	-13.1	-24.7	50.2
(घ) रसायन एवं संबद्ध उत्पाद										
विश्व	10.4	12.3	12.8	12.7	12.1	24.3	7.2	0.9	-18.1	23.8
अमरीका	5.7	14.8	17.2	15.8	17.6	26.8	12.8	7.4	-9.9	45.5
ईयू	9.7	13.0	12.5	12.4	13.0	24.4	7.4	-11.8	-26.4	27.5
अन्य	12.5	11.6	12.2	12.3	11.0	23.7	6.0	4.0	-16.9	18.2
(ड.) चमड़ा एवं चमड़े का उत्पाद										
विश्व	4.4	1.9	1.9	2.0	1.7	8.7	1.5	-5.5	-20.2	14.1
अमरीका	3.7	1.7	1.5	1.6	1.4	-1.5	16.1	-17.8	-24.4	14.5
ईयू	11.4	5.9	6.3	6.7	6.0	9.5	1.0	-2.1	-16.9	8.2
अन्य	1.6	0.7	0.6	0.7	0.7	12.6	-2.1	-9.4	-26.8	31.1
(च) हस्तनिर्मित गलीचा सहित हस्तशिल्प										
विश्व	2.8	0.6	0.5	0.5	0.5	2.3	-25.8	-10.6	-30.4	22.6
अमरीका	6.0	1.6	1.5	1.5	1.4	-1.7	-30.6	-14.7	-32.2	21.6
ईयू	4.4	1.1	1.1	1.1	0.9	1.9	-18.0	-7.5	-29.4	3.2
अन्य	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	10.6	-30.2	-10.6	-29.4	56.4
III पेट्रोलियम, कच्चा तेल एवं उत्पाद										
विश्व	4.3	14.9	15.8	13.3	16.9	46.8	-3.0	2.3	-42.5	66.0
अमरीका	0.0	0.8	2.3	2.2	2.7	214.9	-76.2	180.3	21.5	61.4
ईयू	0.0	10.6	16.9	12.6	17.4	683.2	5.7	45.4	-10.9	67.9
अन्य	7.9	18.6	18.1	15.8	19.5	43.7	-5.0	-3.9	-47.8	64.5
कुल निर्यात										
विश्व	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	20.4	13.6	-3.5	-25.7	30.1
अमरीका	00.0	100.0	100.0	100.0	100.0	12.1	2.0	-7.6	-23.5	30.1
ईयू	00.0	100.0	100.0	100.0	100.0	18.3	13.9	-8.4	-26.8	21.7
अन्य	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	23.5	15.7	-1.3	-25.7	32.6

स्रोत: डीजीसीआईएण्डएस तथा अपनी स्वयं की गणनाएं

टिप्पणी:

[क]वृद्धि दर अमरीकी डालर में

सारणी 7.8 : आयात की जिन्सवार संरचना

जिन्स समूह	प्रतिशत हिस्सा				सीएजीआर	वृद्धि दर (प्रतिशत)[क]			
	2000-01	2009-10	2009-10 (अप्रैल-सित.)	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2000-01 to 2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 (अप्रैल-सित.)	2010-11 (अप्रैल-सित.)
I. खाद्य एवं संबद्ध उत्पाद जिनमें से	**3.3**	**3.7**	**3.5**	**3.2**	**19.3**	**9.1**	**69.0**	**59.8**	**13.7**
1. अनाज	0.0	0.0	0.0	0.0	73.8	-93.3	123.1	-2.7	237.5
2. दलहन	0.2	0.7	0.6	0.5	42.6	-2.4	58.8	47.1	4.2
3. खाद्य तेल	2.6	1.9	1.9	1.8	9.7	34.4	62.3	69.7	17.6
II. ईंधन जिसमें से	**33.5**	**33.2**	**32.5**	**33.2**	**26.0**	**17.7**	**-5.5**	**-39.7**	**28.9**
4. पीओएल	31.3	30.2	29.2	30.1	25.8	17.4	-7.0	-40.8	29.7
III. उर्वरक	**1.3**	**2.3**	**2.6**	**2.4**	**33.3**	**156.8**	**-48.3**	**-55.4**	**14.4**
IV. पूंजी वस्तुएं, जिसमें से	**10.5**	**15.0**	**15.9**	**13.1**	**37.2**	**-3.9**	**-8.2**	**-20.0**	**4.2**
5. इलेक्ट्रिकल एवं मशीनी औजारों को छोड़कर मशीनरी	5.9	7.4	8.0	7.3	33.1	7.7	-10.2	-24.3	15.7
6. इलेक्ट्रिकल मशीनरी	1.0	1.1	1.2	1.0	28.7	27.7	-15.1	-28.9	7.4
7. परिवहन संबंधी उपकरण	1.4	4.1	4.2	2.1	61.1	-34.3	-11.6	-18.1	-36.1
V. अन्य, जिनमें से	**46.3**	**42.6**	**42.5**	**43.2**	**22.6**	**23.8**	**1.3**	**-27.8**	**28.0**
8. रसायन	5.9	5.2	5.6	5.7	22.1	23.0	0.0	-22.9	26.7
9. मोती, कीमती पत्थर अर्द्ध कीमती पत्थर	9.6	5.6	4.3	7.7	7.2	107.7	-2.4	-47.8	128.9
10. सोना और चांदी	9.3	10.3	9.1	8.1	20.8	26.4	32.8	-23.9	12.1
11. इलेक्ट्रिक वस्तुएं	7.0	7.3	8.3	6.3	28.1	15.3	-10.0	-17.7	-5.3
कुल आयात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**25.6**	**20.7**	**-5.0**	**-30.7**	**26.0**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

[क] अमरीकी डालर में विकास दर

I, II, III, IV, और V का योग कुछ अवर्तीकृत मदों के कारण आयातों में जोड़ा नहीं जा सकता है।

2010-11 की पहली छमाही में बहुत अधिक वृद्धि (129 प्रतिशत) प्रतिशत दिखाई दी।

निर्यात विविधता

7.34 वर्ष 2009 में भारत के पास 1 प्रतिशत या दो संख्यात्मक सुमेलित प्रणाली (एचएस) स्तर के कुल 99 सामग्रियों में से 48 में 1 प्रतिशत वैश्विक निर्यात का हिस्सा था, लेकिन 12 मदों में 5 प्रतिशत या अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा है (सारणी 7.9)। इनमें तीन मदों, मोती बहुमूल्य पत्थरों, धातु, सिक्के इत्यादि; मानव निर्मित फिलामेंट; और अयस्क, लौह-चून और भस्म में 2008 की तुलना में 2009 में अधिक 0.5 प्रतिशत या अधिक अंक के ग्लोबल हिस्से में बढ़ोतरी हुई थी; छः मदें जिसमें सिल्क; कॉरपेट

सारणी 7.9 : विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा: जिन्सवार (5% से अधिक हिस्सा)

क्र. सं.	उत्पाद कोड	उत्पादन लेबल	2005	2006	2007	2008	2009	हिस्से में परिवर्तन 2009/2008
1	71	मोती, बहुमूल्य पत्थर, धातु, सिक्के आदि	8.2	6.5	6.6	5.7	10.1	4.4
2	50	सिल्क	12.5	11.4	10.5	10.2	9.7	-0.5
3	57	कार्पेट एवं अन्य टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग	9.0	9.6	8.7	8.4	8.4	0.0
4	13	लाख, गम, रेसीन, वनस्पति सार एवं सत्त	11.4	10.6	9.5	9.7	7.9	-1.8
5	52	कॉटन	5.5	6.8	8.5	8.6	7.7	-0.9
6	53	वनस्पति टेक्सटाइल फाइबर, पेपर यार्न, बुने हुए फेब्रिक	4.8	4.2	4.6	6.1	6.3	0.2
7	63	अन्य निर्मित टेक्सटाइल वस्तुएं, सेंट्स, बुने हुए कपड़े आदि	7.0	6.4	5.7	5.4	5.5	0.1
8	54		2.5	2.6	2.9	3.7	5.1	1.4
9	67	बर्ड स्किन, पंख, बनावटी फूल, मानव बाल	3.4	4.4	5.0	5.0	5.1	0.1
10	14	वनस्पति प्लेटिंग सामग्री, वनस्पति उत्पाद	5.1	4.5	4.8	5.4	5.1	-0.4
11	09	कॉफी, चाय, मेट एवं मसाले	4.7	5.0	5.2	5.3	5.1	-0.3
12	26	अयस्क, स्लैग, राख	6.8	4.8	4.8	4.5	5.0	0.5

स्रोत: यूएन-आईटीसी व्यापार मानचित्र डाटा, 2009 पर आधारित राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एनसीटीआई) डाटा से संगणित।

और अन्य फ्लोर कवरिंग कपड़ा; लाख, गोंद, रेजिन, वनस्पति रस और निष्कासित नेस; काफी, चाय, मेट और मसालों ने 2008 की तुलना में 2009 में ग्लोबल शेयर खोए हैं। व्यापारिक क्रियाकलापों में वृद्धि से मोती, बहुमूल्य पत्थरों, धातुओं, सिक्कों इत्यादि के शेयर में दुगुनी बढ़ोतरी देखी जा रही हैं और वैकल्पिक उत्पादों और प्रतिस्पर्द्धी देशों से फसल बर्बाद होने के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धा के कारण लाख, रेजिन, वनस्पति रस और सत्व, में करीब 2 प्रतिशत की गिरावट आयी है। शेष 38 मदों से 2008 की तुलना में में 2009 में 11 ने अपना हिस्सा गंवाया है।

व्यापार की दिशा

7.35 शीर्ष 15 व्यापारिक सहयोगियों के हिस्से के साथ इस दशक के प्रारम्भिक अवधि में बदलाव के बाद भारतीय व्यापार की दिशा संबंधी पैटर्न में 2000-01 की तुलना में 2007-08 में 5.5 प्रतिशत से लेकर 60.3 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी हुई है, जिसमें इसमें अधिक बदलाव नहीं आया क्योंकि शीर्ष 15 देश अभी भी 2009-10 और 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर) (सारणी 7.10) में लगभग 60 प्रतिशत हिस्से पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। वर्ष 2010-11 के प्रारम्भ में इनका हिस्सा 59.8 प्रतिशत था। भारतीय व्यापार के दिशानिर्देश में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह है कि अमेरिका, जो 2007-08 में पहले स्थान पर था, 2008-09 तीसरे स्थान पर पहुंच गया है, अब यूएई-चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बन कर उभर रहा है। यह स्थिति 2009-10 तक बनी रही तथा 2010-11 के प्रारम्भ तक बनी हुई है। यह मुख्य रूप से यूएई को रत्न और आभूषण मदों के पीओएल के भारत आयात निर्यात के कारण हुआ है। 2009-10 और 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर) दोनों में, भारत का यूएई के साथ निर्यात आयात से अधिक है, जबकि चीन के साथ भारतीय निर्यात आयात से कम है। यूएई के साथ उच्च और बढ़ते व्यापार का कारण कुछ हद तक चक्रीय व्यापार के कारण भी हो सकता है।

7.36 सारणी 7.10 में आयात-निर्यात दर यह दर्शाती है कि इसके शीर्ष 15 व्यापारिक सहयोगियों में भारत का 2009-10 और 2010-11 के पूर्वार्द्ध में पांच देशों अर्थात् यूएई, यूएसए, सिंगापुर, यूके और हांगकांग के साथ द्विपक्षीय व्यापारिक अधिशेष थे। 2007-08 में अमेरिका और सिंगापुर के साथ भारतीय व्यापार घाटा इसके बाद अधिशेष व्यापार में बदल गया। 2008 में हांगकांग का आयात-निर्यात दर घट गया था, हालांकि इसे 2009-10 में पुन: प्राप्त कर लिया गया। चीन के संदर्भ में भारतीय आयात निर्यात दर कम ही नहीं बल्कि 2009-10 में 0.4 की बढ़ोतरी लगभग 0.3 तक स्थिर हो गयी और 2010-11 के पूर्वार्द्ध में फिर 0.3 की गिरावट हुई।

7.37 यूएई ने 2008-09 और 2009-10 में भारतीय निर्यात के क्रमश: 13.2 प्रतिशत और 73.4 प्रतिशत के निर्यात हिस्से से शीर्षस्थ गंतव्य के रूप अमेरिका को हटाकर अपना स्थान बना लिया है। वर्ष 2009-10 में, शीर्ष दो गंतव्यों अर्थात् यूएई और अमरीका को भारतीय निर्यात वृद्धि क्रमश: (-)2.1 और (-)7.6 प्रतिशत दर्ज की गई।

सारणी 7.10 : प्रमुख व्यापार साझेदारों के साथ भारत का व्यापार तथा आयात-निर्यात अनुपात

		कुल व्यापार में हिस्सा					आयात-निर्यात अनुपात [क]				
		2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 (अप्रैल-सित.)	2010-11 (अप्रैल-सित.)	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10 (अप्रैल-सित.)	2010-11 (अप्रैल-सित.)
1	यू॰ए॰ई॰	7.0	9.9	9.3	8.8	9.9	1.2	1.0	1.2	1.5	1.2
2	चीन	9.2	8.6	9.1	9.1	9.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3
3	अमेरिका	10.1	8.1	7.8	8.6	7.6	1.0	1.1	1.2	1.0	1.4
4	साउदी अरेबिया	5.6	5.1	4.5	4.4	4.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
5	जर्मनी	3.6	3.8	3.4	3.6	3.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
6	सिंगापुर	2.5	2.6	3.3	2.7	3.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0
7	ईरान	3.7	3.3	3.0	3.2	3.0	0.9	1.1	1.2	1.2	1.3
8	हांगकांग	2.2	2.6	3.0	2.9	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
9	कोरिया रिपब्लिक	3.1	3.0	2.9	3.2	2.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
10	यू॰के॰	2.2	2.7	2.7	2.6	3.0	2.3	1.0	1.7	2.3	1.4
11	अस्ट्रेलिया	2.1	2.6	2.6	2.4	2.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
12	स्विटजरलैंड	1.7	1.9	2.5	2.7	2.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
13	जापान	2.8	2.6	2.3	2.4	2.1	1.4	1.1	1.4	1.4	1.5
14	मलेशिया	2.5	2.2	2.2	2.2	2.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7
15	नाईजीरिया	2.1	2.1	2.1	2.0	2.4	1.0	0.8	0.6	0.6	0.6
	जोड़ (1 से 15)	60.3	61.0	60.5	60.9	59.8	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
	कुल व्यापार	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.6**	**0.7**

स्रोत: डीजीसीआई एण्ड एस डाटा से संगणित।

टिप्पणी : 0 से 1 के बीच आयात एवं निर्यात के सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का आयात निर्यात से अधिक है तथा एक से अधिक सहगुणांक का मतलब यह है कि भारत का निर्यात आयात से अधिक है।

7.38 क्षेत्रवार, वर्ष 2010-11 के पहली छमाही में भारतीय निर्यात के आधे से अधिक (53.5 प्रतिशत) एशिया (आसियान सहित) के साथ था जो 2001-02 में लगभग 40 प्रतिशत था। वर्ष 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर) के दौरान एशिया (आसियान सहित) की 29.2 प्रतिशत और यूरोप की 23.3 प्रतिशत निर्यात बढ़ोतरी हुई। भारत का दक्षिण एशिया देशों के साथ व्यापारिक निर्यात 29.2 प्रतिशत बढ़ा।

7.39 वर्ष 2010-11 (अप्रैल-सितम्बर) में, एशिया और आसियान कुल निर्यात के 61.5 प्रतिशत भारतीय निर्यात का प्रमुख स्रोत बनी हुई हैं। देशों के क्रम में देखें तो यूएई (7.5 प्रतिशत), सउदी अरब (6 प्रतिशत) और अमेरिका (5.3 प्रतिशत) के क्रम में चीन भारतीय कुल आयात में 12 प्रतिशत हिस्सा रखने वाला सबसे बड़े स्रोत के रूप में बना हुआ है। भारत के शीर्ष 15 व्यापारिक सहयोगियों में 13 की आयात-वृद्धि सकारात्मक थी; अमेरिका और ईरान अपवाद हैं।

सेवा व्यापार

7.40 हाल के वर्षों में, सेवा व्यापार का केन्द्र बिन्दु वस्तुओं के व्यापार के सुसाध्यीकरण से हटा है क्योंकि यह क्षेत्र अब नई संभावनाओं को खोलते हुए चार आपूर्ति तरीकों में सेवा व्यापार सहित अपने आप में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में उभरा है। दूरसंचार और कम्प्यूटर तकनीकी के एकीकरण ने सभी व्यापारिक सेवाओं को सीमा के आर-पार तक यर्थाथ बना दिया है। वस्तुत: सभी व्यापारिक सेवाएं अब सीमा से आगे बढ़ गई है। भूमण्डलीकरण की ओर झुकाव, उदारवादी नीतियों को बढ़ावा और नियमित अवरोध के निष्कासन से, अन्तर्राष्ट्रीय निवेश और सेवाओं में व्यापार को लगातार बढ़ावा मिला है।

सेवाओं में विश्व व्यापार

7.41 व्यापारिक सेवाओं के 3.35 ट्रिलियन अमेरिकी डालर का विश्व निर्यात भारत और चीन के अपवाद के साथ, जो खुद 12 शीर्ष निर्यातकों में शामिल है, 2009 में विकसित देशों के प्रभुत्व में था। पण्य व्यापार के मामले की तरह, भारत ने व्यापारिक सेवा व्यापार में भी अपने स्थान में सुधार किया है। 2009 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा प्रकाशित न्यूनतम 'अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2010' के अनुसार सेवाओं में विश्व निर्यात और आयात वृद्धि 2009 में (-)12 प्रतिशत गिरी है। यह गिरावट अधिकांश प्रमुख क्षेत्र जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप, और एशिया में कमोबेश समान थी। यूएस, ईयू और जापान में व्यापारिक सेवाओं में आयात वृद्धि क्रमश: (-)9 प्रतिशत, (-)13 प्रतिशत, और (-)10 प्रतिशत तक गिरी है। जबकि भारत की व्यापारिक सेवाओं के आयात वृद्धि और निर्यात वृद्धि क्रमश: (-)9 प्रतिशत और (-)15 प्रतिशत और चीन की क्रमश: 0 प्रतिशत और (-)12 प्रतिशत थी। हालांकि 2009 में विश्व पण्य निर्यात में चीन, जो प्रथम स्थान रखता है, की तुलना में भारत 21वें स्थान पर है और व्यापारिक निर्यात सेवाओं में चीन के पांचवें स्थान की तुलना में भारत 12वें स्थान पर है।

7.42 व्यापारिक सेवाओं की तीन वृहद वर्गों अर्थात परिवहन, यात्रा और अन्य व्यापारिक सेवाओं में 2009 (सारणी 7.11) के निर्यात वृद्धि में ह्रास/गिरावट दिखाई दी। सेवाओं के शीर्ष निर्यातकों/आयातकों में से (ईयू-27 को एकल इकाई के रूप में लिया गया), भारत का अन्य वाणिज्यिक सेवाओं, कम्प्यूटर और सूचना सेवाएं, संचार सेवाएं और वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजनात्मक सेवाओं में प्रथम पांच देशों में स्थान है (सारणी 7.12)।

7.43 विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2010 के अनुसार, 2009 में सभी वाणिज्यिक सेवा क्षेत्र ग्लोबल संकट से प्रभावित थी, पर एक समान नहीं। विश्व व्यापार में गिरावट के प्रतिरूप परिवहन सेवा वृद्धि में भी गिरावट आयी। वित्तीय सेवाएं वित्तीय बाजारों में आई हलचलों के कारण गंभीर रूप से प्रभावित हुई जिसका परिणाम यह हुआ कि 2009 में वित्तीय सेवाओं के विश्व निर्यात में 15 प्रतिशत की गिरावट आयी हालांकि वे वर्ष के पिछले कुछ महीनों में धीरे-धीरे इनमें पुन: सुधार होना शुरु हो गया है। यूरोप की वित्तीय सेवाएं आर्थिक संकट से सबसे ज्यादा प्रभावित थी। ईयू का वित्तीय सेवाओं का निर्यात 2009 में से 19 प्रतिशत नीचे गिर कर 133 बिलियन अमेरिकी डालर हो गया है। वित्तीय सेवाओं के दूसरा सबसे बड़ा विश्व निर्यातक संयुक्त राष्ट्र, और हांगकांग में यह गिरावट

सारणी 7.11 : प्रमुख श्रेणियों के अनुसार वाणिज्यिक सेवाओं का विश्व निर्यात 2008

	मूल्य (अमरीकी बिलियन डालर में)	वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन			
	2009	2000-09	2007	2008	2009
वाणिज्यिक सेवाएं	3350	9	20	13	-12
परिवहन	700	8	20	17	-23
यात्रा	870	7	15	10	-9
अन्य वाणिज्यिक सेवाएं	1780	12	23	12	-9

स्रोत : डब्ल्यू टी ओ

सारणी 7.12 : सेवाओं के निर्यात/आयात में भारत का क्षेत्रवार रैंक एवं हिस्सा

		रैंक	हिस्सा		प्रतिशत परिवर्तन
		2009	2000	2009	2009
परिवहन सेवाएं	निर्यात	13	0.6	1.5	-5
	आयात	13	2.1	4.2	-17
यात्रा सेवाएं	निर्यात	14	0.7	1.2	-10
	आयात				
अन्य वाणिज्यिक सेवाए	निर्यात	4		3.7	-17
	आयात	8		2.4	0
संचार सेवाएं*	निर्यात	4		0.6	43
	आयात	11		1.5	-11
निर्माण सेवाएं*	निर्यात**	12		1	-5
	आयात**	13		1.5	178
बीमा सेवाएं*	निर्यात	7			
	आयात	7		5.4	17
वित्तीय सेवाएं*	निर्यात	7			
	आयात	5		2.1	-1
कम्प्यूटर एवं सूचना सेवाएं*	निर्यात	2		1.8	163
	आयात**	4		1.3	19
अन्य व्यवसाय सेवाएं*	निर्यात**	6		0.6	-42
	आयात**	6		1.4	40
वैयक्तिक, सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सेवाएं*	निर्यात**	5		7.7	-6
	आयात	12		9.4	

स्रोत : डब्ल्यूटीओ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2010 से संकलित।
टिप्पणी : *डाटा 2008 से संबंधित है; **डब्ल्यूटीओ सचिवालय का अनुमान।

7 प्रतिशत थी। 2010 के शुरुआत में, वित्तीय सेवाओं के निर्यात में वृद्धि देखी गई। 2010 की पहली छमाही का अनुमान सभी देशों में सुधार दर्शाता है। 2008 के सबसे गतिशील क्षेत्र निर्माण की वृद्धि में भी तेजी से गिरावट देखी गई है। कम्प्यूटर और सूचना सेवाओं की तरह रायल्टीस और लाइसेंस अधिक लोचदार थे। कम्प्यूटर और सूचना सेवाओं का विश्व निर्यात 2008 में 23 प्रतिशत के रिकार्ड वृद्धि के बाद, 2009 में इसमें 6 प्रतिशत की कमी आयी। कम्प्यूटर और सूचना सेवाएं यूरोप में 9 प्रतिशत और सीआईएस में 14 प्रतिशत गिरी तब उत्तरी अमेरिका में वह स्थिर हुई और एशिया में 2 प्रतिशत की गिरावट आई। विदेशी पर्यटकों के आगमन में 4 प्रतिशत की गिरावट सहित अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन में विश्वस्तरीय गिरावट दर्शाते हुए 2009 में, विश्व पर्यटन निर्यात में 9 प्रतिशत की गिरावट आयी है। यह गिरावट मुख्य रूप से यूरोप (-13 प्रतिशत) उत्तरी अमरीका प्रक्रिया (-11), और सीआईएस (-22 प्रतिशत) देखी गई थी। एशियाई अर्थव्यवस्था 3 प्रतिशत गिरावट के साथ कम प्रभावित रही। विश्व पर्यटन संगठन के पूर्वानुमान के अनुसार 2010 में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या में 3-4 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी, यह दर्शाता है कि विश्व पर्यटन काफी तेजी से उभर रहा है।

7.44 वाणिज्यि सेवाओं के आयात में, भारत 2005 और 2008 में 13वें स्थान से 2009 में 12वें स्थान पर पहुंच गया और इसका हिसा 2.5 प्रतिशत था। संयुक्त राज्य, यूरोपीय संघ, चीन और जापान विश्व में सेवाओं के प्रमुख निर्यातक हैं।

भारत का सेवा व्यापार

7.45 भारत और चीन दो महत्वपूर्ण विकासशील देश हैं जो सेवाओं के व्यापार क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तथापि भारत में विभिन्न सेवाओं की वृद्धि का पैटर्न अन्य देशों से भिन्न है। वाणिज्यिक सेवाएं जहां अधिकांश शीर्ष सेवा निर्यातकों के लिए प्रमुख श्रेणी हैं, वहीं भारतीय मामले में इसका हिस्सा आनुपातिक रूप से अन्य की अपेक्षा अधिक है। 2008 में यह 77.4 प्रतिशत था जिसकी तुलना में यूएसए में 56.5 प्रतिशत, यूरोपीय संघ में 54.8 प्रतिशत, चीन में 45.9 प्रतिशत और जापान में 60.6 प्रतिशत था। इस प्रकार अनेक गतिशील सेवाओं का समावेश करने वाली यह श्रेणी भारत के लिए महत्वपूर्ण है। यात्रा का 11.5 प्रतिशत का हिस्सा अधिकांश अन्य देशों की तुलना में कम है। यूएस और चीन का हिस्सा भारत की तुलना में दुगने से भी अधिक है। परिवहन के क्षेत्र में भी, भारत का हिस्सा अनेक अग्रणी सेवाओं के निर्यातकों की तुलना में आधे से कम है, जो अंशत: पण्य व्यापार में भारत की न्यूनतर मात्रा और अंशत: भारत के निर्यात व्यापार में भारत के नौवहन क्षेत्र की अपेक्षाकृत न्यूनतर भागीदारी के कारण है। इस प्रकार, सेवाओं के निर्यातों की संरचना भारत में नौवहन और यात्रा सेवाओं को विकसित करने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को उजागर करती है। अन्य सेवा कारोबारी देशों की तुलना में भारत के आयातों की संरचना, विशेषकर 2009-10 में भी अन्य वाणिज्यिक सेवाओं के अपेक्षाकृत उच्चतर महत्व, को दर्शाती है।

भारत का सेवा निर्यात

7.46 भारत, जो सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत सीएजीआर, जो 2004-05 से 2009-10 के दौरान सेवा भिन्न क्षेत्र के लिए 6. 7 प्रतिशत की अपेक्षा अधिक है, के साथ सेवाओं के प्रभुत्व वाले सघउ वृद्धि की दिशा में बढ़ रहा है। यह सेवाओं के प्रभुत्व वाली निर्यात वृद्धि की ओर भी बढ़ रहा है, जिसमें 2004-05 से 2009-10 के दौरान सेवाओं के लिए 16.7 प्रतिशत सीएजीआर था 2000-01 से 2006-07 के दौरान सीएजीआर 28.7 प्रतिशत था) जो इसी अवधि में पण्य निर्यात के लिए 16.4 प्रतिशत की तुलना में थोड़ा सा अधिक था। सेवाओं का निर्यात पूर्व वर्ष की तुलना में 17.3 प्रतिशत की साधारण वृद्धि के साथ 2008-09 में 106 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया। वैश्विक मंदी के परिणामस्वरूप, 2009-10 में (-)9.6 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि के साथ वे 95.8 बिलियन अमरीकी डालर तक गिर गए। सेवा निर्यात की विविध मद जिसका कुल सेवा निर्यात में तीन-चौथाई हिस्सा है, में 2010-11 की पहली छमाही में 28.2 प्रतिशत की वृद्धि के साथ थोड़ा सा सुधार हुआ। सॉफ्टवेयर सेवाओं का हिस्सा 2010-11 की पहली छमाही में 2009-10 की इसी अवधि में 50.8 प्रतिशत से गिर कर 45.7 प्रतिशत हो गया। यह 2010-11 की पहली छमाही में 14.7 प्रतिशत की साधारण वृद्धि और सॉफ्टवेयर इतर सेवा निर्यात के पुनरोत्थान के परिणामस्वरूप था। सॉफ्टवेयर इतर सेवा निर्यात, जिसमें 2008-09 में (-)41.2 प्रतिशत की उच्च ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुई थी, में 56.9 प्रतिशत की उच्च वृद्धि के साथ इसका हिस्सा बढ़कर 29.5 प्रतिशत तक हो गया। 2000-01 से 2007-08 के दौरान 33. 9 प्रतिशत के सीएजीआर वाले इस सेक्टर का पुनरोत्थान एक अच्छा लक्षण है, यद्यपि यह आंशिक रूप से आधार प्रभाव के कारण है। सॉफ्टवेयर-इतर सेवाओं में व्यवसायिक सेवाओं का बढ़ता हिस्सा उल्लेखनीय है। व्यवसायिक सेवाओं और वित्तीय सेवाओं दोनों में 111.4 प्रतिशत और 64.9 की बहुत उच्च वृद्धि दर्ज हुई। आधार प्रभाव से अधिक, यह वैश्विक सुधार के बाद इन निर्यातों के पुनुरोत्थान के कारण था (सारणी 7.13)। यात्रा सेवाओं के हिस्से में 2000-01 में 21.5 प्रतिशत से 2010-11 की पहली छमाही में 11.4 प्रतिशत तक की गिरावट चिन्ता का विषय है। यह इस तथ्य को दर्शाता है कि हम भारत में असीम पर्यटन की संभावनाओं का दोहन अभी तक नहीं कर पाए हैं।

भारत का सेवा आयात

7.47 वाणिज्यिक सेवाओं का आयात हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण हो गया है और यह 2008-09 में 52 बिलियन अमरीकी डालर और 2009-10 में 60 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया है। परन्तु 2008-09 में इसमें 1.1 प्रतिशत की निम्न वृद्धि और 2009-10 में 15.3 प्रतिशत की साधारण वृद्धि हुई (सारणी 7. 14)। व्यावसायिक सेवाएं सेवा आयात की सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रेणी हैं, जिसके बाद परिवहन और यात्रा का स्थान है। व्यावसायिक सेवाओं की आयात वृद्धि जो 2008-09 में -7.5 प्रतिशत तक गिर गई थी, 2009-10 में बढ़कर 17.8 प्रतिशत हो गई और 2010-11 की पहली छमाही में 62.9 प्रतिशत की बहुत अधिक वृद्धि हुई। परिवहन और यात्रा की आयात वृद्धि जो 2009-10 में

सारणी 7.13 : भारत का सेवा निर्यात

क्र. सं.	वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत)				सीएजीआर 2000-01 से	विकास दर *			
				अप्रैल-सितम्बर					अप्रैल-सितम्बर	
		2000-01	2009-10	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10	2010-11
1.	यात्रा	21.5	12.4	11.5	11.4	18.3	-4.0	8.9	-5.2	26.2
2.	परिवहन	12.6	11.7	11.6	11.5	25.5	12.9	-1.2	-10.3	26.6
3.	बीमा	1.7	1.7	1.8	1.5	29.4	-13.2	12.7	6.2	10.4
4.	जीएनआईई	4.0	0.5	0.5	0.4	-9.2	17.6	13.2	-5.2	9.5
5.	विविध	60.3	73.8	74.7	75.2	31.6	22.3	-13.8	-16.4	28.2
	क) साफ्टवेयर सेवाएं	39.0	51.9	50.8	45.7	30.2	14.9	7.4	-8.2	14.7
	ख) गैर साफ्टवेयर सेवाएं	21.3	21.9	24.0	29.5	33.9	33.5	-41.2	-36.6	56.9
	जिसका									
	i) व्यवसाय सेवाएं	2.1	11.9	11.6	19.3	75.0	10.9	-38.9	-46.4	111.4
	ii) वित्तीय सेवाएं	2.1	3.9	4.2	5.5	37.5	37.7	-15.6	-19.2	64.9
	iii) संचार सेवाएं	7.0	1.3	1.7	1.3	11.3	-4.6	-46.5	-42.0	2.3
	कुल सेवा निर्यात	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**27.8**	**17.3**	**-9.6**	**-16.8**	**27.4**

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं
टिप्पणी: * वृद्धि दर अमरीकी डालर में
जीएनआईई = सरकार अन्यत्र शामिल नहीं

सारणी 7.14 : भारत का सेवा आयात

क्र. सं.	वस्तु समूह	हिस्सा (प्रतिशत)				सीएजीआर 2000-01 से	विकास दर *			
				अप्रैल-सितम्बर					अप्रैल-सितम्बर	
		2000-01	2009-10	2009-10	2010-11	2007-08	2008-09	2009-10	2009-10	2010-11
1.	यात्रा	19.2	15.6	17.8	14.0	18.6	1.8	-0.9	-9.9	15.6
2.	परिवहन	24.4	19.9	20.3	18.4	18.3	11.3	-6.9	-29.4	33.2
3.	बीमा	1.5	2.1	2.7	1.9	24.7	8.3	13.8	22.9	6.3
4.	जीएनआईई	2.2	0.9	0.9	1.0	2.4	111.2	-33.7	13.2	49.4
5.	विविध	52.6	61.5	58.3	64.7	21.1	-4.8	32.5	9.2	63.1
	क) साफ्टवेयर सेवाएं	4.1	2.4	3.4	3.2	28.2	-23.6	-42.7	-53.4	39.9
	ख) गैर साफ्टवेयर सेवाएं	48.6	59.1	55.0	61.5	20.4	-2.4	40.1	18.9	64.5
	जिसका									
	i) व्यवसाय सेवाएं	7.0	30.1	32.1	35.5	48.9	-7.5	17.8	10.9	62.9
	ii) वित्तीय सेवाएं	13.5	7.7	8.0	9.1	6.8	-5.6	56.9	24.2	68.0
	iii) संचार सेवाएं	0.9	2.3	2.4	1.4	31.4	26.5	24.6	13.0	-14.2
	कुल सेवा आयात	100.0	100.0	100.0	100.0	19.8	1.1	15.3	-4.7	46.9

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं

टिप्पणी: * वृद्धि दर अमरीकी डालर में जीएनआई = सरकार अन्यत्र शामिल नहीं

गिर गई थी, 2010-11 की पहली छमाही में सकारात्मक हो गई। वित्तीय सेवाओं का आयात 68 प्रतिशत तक बढ़ गया।

सेवाओं में व्यापार का संतुलन

7.48 मुद्रा स्फीति के साथ-साथ अत्यधिक पण्य व्यापार घाटा, जो विकास की गति को पटरी से उतार रहे हैं, बढ़ती हुई चिन्ता का विषय है। तथापि एक तथ्य, जिसके बारे में कम जानकारी है, यह है कि गिरता हुआ सेवा व्यापार, पहले की भांति सहारा बनने के स्थान पर, चालू खाता घाटे के मोर्चे पर समस्याओं में इजाफा कर रहा है। सेवा व्यापार अधिशेष जो इस दशक में लगातार बढ़कर 2008-09 में 53.9 बिलियन अमरीकी डालर पहुंच गया था, 2009-10 के वैश्विक संकट के वर्ष में अत्यधिक गिर कर 35.7 बिलियन हो गया। इसका कारण सॉफ्टवेयर-इतर सेवाओं, विशेषकर कारोबारी सेवाओं के निर्यात में बेतहाशा कमी, सॉफ्टवेयर सेवाओं की धीमी वृद्धि और सॉफ्टवेयर-इतर सेवाओं, विशेषकर कारोबारी और वित्तीय सेवाओं के आयात में वृद्धि था। निम्न सेवा व्यापार अधिशेष स्थिति 2010-11 के पूर्वार्ध में जारी रही। यह सॉफ्टवेयर-इतर सेवाओं, विशेषकर कारोबारी और वित्तीय सेवाओं के आयात में अचानक वृद्धि के कारण था, जिसने कारोबारी और वित्तीय सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को प्रभावहीन कर दिया। यदि यह स्थिति इस वर्ष के उत्तरार्द्ध में जारी रहती है तो हमें इस तथ्य को अंगीकार करना होगा कि अभी तक सेवा क्षेत्र द्वारा व्यापार संतुलन के लिए दिया जा रहा अतिरिक्त अवलम्बन उपलब्ध नहीं होगा। कारोबारी और वित्तीय सेवाओं के बढ़ते हुए आयात की वृद्धि पर प्रभाव का भी मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है। (देखें सारणी 7.15)

सारणी 7.15 : भारत का सेवाओं में निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन

(अमरीकी बिलियन डालर)

	निर्यात	आयात	शेष
2000-01	16.3	14.6	1.7
2001-02	17.1	13.8	3.3
2002-03	20.8	17.1	3.6
2003-04	26.9	16.7	10.1
2004-05	43.2	27.8	15.4
2005-06	57.7	34.5	23.2
2006-07	73.8	44.3	29.5
2007-08	90.3	51.5	38.9
2008-09	106.0	52.0	53.9
2009-10	95.8	60.0	35.7
2009-10 (अप्रैल-सितम्बर)	43.8	24.7	19.1
2010-11 (अप्रैल-सितम्बर)	55.7	36.2	19.5

स्रोत : आरबीआई डाटा पर आधारित गणनाएं

सेवाओं में व्यापार संबंधी नीतियां और अवरोध

7.49 वैश्विक मंदी के परिप्रेक्ष्य में, सेवा क्षेत्र की सहायता के लिए कुछ उपाय किए गए थे। इनमें 2010-11 तक भारत के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कों और निर्यातोन्मुख इकाइयों हेतु समापन खंडों का विस्तार तथा 'सर्व्ड फ्राम इंडिया' योजना के तहत

होटलों को शुल्क माफी हकदारिता को दुगना करना शामिल है। सेवा क्षेत्र के लिए एक समान्वित और समरूप प्रयास की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान समय में सेवा क्रियाकलाप छितरे हुए हैं और सरकार के अलग-अलग विभागों के दायरे में आते हैं। (कृपया बॉक्स 7.6 भी देखें)। सेवाओं में व्यापार हेतु अनेक अवरोध भी हैं। इनमें राज्य-स्तरीय लाइसेंसिंग और अमरीका में कारोबारी सेवाओं और आईटी सेवाओं के मामले में 'अमेरिकन खरीदें' प्रावधान; अमरीका में मुद्रा नियंत्रक के कार्यालय और कुछ राज्य बैंकिंग पर्यवेक्षकों की वित्तीय सेवाओं के मामले में उनके अपने देश में उनके द्वारा रखी जा रही चुकता पूंजी के अतिरिक्त 'आस्ति वचनबद्धता' बनाए रखने की अपेक्षा; यूएस बीमा बाजार का 56 विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में विभक्तीकरण और अनेक मोर्चों पर प्रत्यक्ष भेदभाव; परिवहन और संबंधित सेवाओं के मामले में प्रतिबंध और अमरीका तथा अन्य अर्थव्यवस्थाओं में हाल की संरक्षणवादी नीतियां जो अन्य देशो को बाजार पहुंच पर रोक लगाते हैं। सेवाओं में व्यापार के लिए बाजार पहुंच अवरोधों को हटाने के लिए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर वार्ता करने की आवश्यकता है।

व्यापार नीति

अद्यतन व्यापार नीतिगत उपाय

7.50 सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2009-10 और 2010-11 में किए गए व्यापार नीतिगत उपाय निर्यात की बहाली और निर्यात संबंधित रोजगार पर केन्द्रित थे। सरकार ने राजकोषीय प्रोत्साहनों, संस्थागत परिवर्तनों, प्रक्रियात्मक यौक्तिकीकरण, और पूरे विश्व में बढ़ी हुई बाजार पहुंच तथा निर्यात बाजारों के विविधीकरण सहित अनेक नीतिगत उपाय किए। निर्यातों से संबंधित अवसंरचना में सुधार; लेन-देन लागतों को नीचे लाना और सभी अप्रत्यक्ष करों और उद्ग्रहणों की पूरी वापसी उपलब्ध कराना, तीन प्रमुख केन्द्र बिन्दु थे। (देखें बॉक्स 7.3)

7.51 देश में मुद्रास्फीति को काबू करने के लिए कुछ व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय निम्नलिखित हैं:

- आयात शुल्क चावल, गेहूं, दालें, खाद्य तेल (कच्चा), मक्खन और घी के लिए घटाकर शून्य और परिष्कृत और हाइड्रोजेनेटेड तेलों और वनस्पति तेलों के लिए 7.5 प्रतिशत किया गया;
- खुले सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत कच्चे चीनी को शून्य शुल्क पर आयात की अनुमति दी गई;
- सफेद/परिष्कृत चीनी के आयात की अनुमति दी गई। यह सुविधा बिना किसी परिमाणात्मक सीमा के 31 दिसम्बर 2010 तक बढ़ा दी गई है।
- सभी आयातित कच्ची चीनी और सफेद/परिष्कृत चीनी के संबंध में लेवी देनदारी हटाई गई।
- गैर-बासमती चावल, खाद्य तेल (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर और दालों (काबुली चना के अतिरिक्त) के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
- प्याज (दिसम्बर 2010 के लिए 1200 डालर प्रति टन) और बासमती चावल (900 डालर पीएमटी) के निर्यात के नियमन के लिए न्यूनतम निर्यात मूल्य का प्रयोग किया गया।
- 22 दिसम्बर 2010 से और अगले आदेश तक प्याज (सभी किस्में) के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई। इसमें बंगलौर रोज ओनियन और कृष्णापुरम ओनियन चाहे वह ताजा हो, चिल्ड, फ्रोजन, कच्चे तौर पर तैयार अथवा सुखाया हुआ प्याज शामिल है परन्तु इसमें कटा हुआ, अथवा चूर्ण रूप में तैयार किया गया प्याज शामिल नहीं है।
- 21 दिसम्बर 2010 से प्याज और छोटा प्याज को मूल सीमा शुल्क से पूरी छूट दी गई। इसके परिणामस्वरूप, इन मदों को 4 प्रतिशत से विशेष अतिरिक्त शुल्क, शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर से भी छूट मिली। यह छूट खुली हुई है और इसमें समापन तारीख निर्धारित करने वाली कोई वैधता खण्ड नहीं है।

राज्यवार निर्यातों का संवर्धन करने की नीति

7.52 वस्तुओं के निर्यात के उद्गम के राज्य संबंधी आंकड़ों में यथापरिलक्षित राज्य-वार निर्यात स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र और गुजरात का प्रभुत्व दर्शाते हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश निर्यातक राज्यों की दूसरी पंक्ति में आते हैं। 2009-10 में, सभी राज्यों से निर्यातों की वृद्धि हरियाणा, केरल, गोवा और राजस्थान के अतिरिक्त सभी राज्यों से ऋणात्मक थी। उच्च ऋणात्मक निर्यात वृद्धि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और कर्नाटक में दर्ज हुई। 2010-11 की पहली छमाही में, केरल को छोड़कर सभी गंत्तव्यों को निर्यात वृद्धि सकारात्मक थी (सारणी 7.16)। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना की निर्यात अवसंरचना और सम्बद्ध क्रियाकलाप के विकास हेतु राज्यों को सहायता की योजना के अधीन परिव्यय बढ़ाकर 3793 करोड़ रुपए किया गया।

बाजार पहुंच कार्यक्रम (एमएआई) और बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजनाएं

7.53 बाजार पहुंच कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में की गई थी जिसका उद्देश्य सुस्थिर आधार पर भारत के निर्यातों के लिए प्रेरक के रूप में कार्य करना था। यह योजना विशिष्ट बाजार और विशिष्ट उत्पाद के लिए विशिष्ट कार्यनीति विकसित करने के लिए उत्पाद केन्द्रित-देश केन्द्रित दृष्टिकोण पर तैयार की गई थी। बेहतर समन्वय, सामंजस्य हेतु और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा भारत के निर्यात संवर्धन गतिविधियों में सहुलियत प्रदान करने के उद्देश्य से हाल ही में एक ''चुनौती निधि'' स्थापित की

बॉक्स 7.3 : व्यापार संबंधी नीतिगत उपाय

बाजार और उत्पाद विविधीकरण तथा बाजारों का विस्तार

- निर्यातों के 3 प्रतिशत पर ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रोत्साहन सहित फोकस मार्केट स्कीम के तहत 27 नए बाजार जोड़े गए।
- 2 प्रतिशत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के प्रोत्साहन सहित मार्केट लिंक्ड फोकस प्रोडक्ट स्कीम का उनके बाजारों से संबद्ध बड़ी संख्या में उत्पादों को शामिल करके काफी अधिक विस्तार किया गया।
- सम्पूर्ण अफ्रीका, लैटिन अमरीका और ओसिनिया का काफी बड़ा हिस्सा एफएमएस और एमएलएफपीएस के अंतर्गत कवर किया गया (अगस्त 2009 में एफटीपी 2009-14 को जारी करते समय 13 देशों को एमएलएफपीएस के अंतर्गत जोड़ा गया और दो देशों को जनवरी 2010 में जोड़ा गया)।
- एफएमएस के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहन को 2.5 प्रतिशत से 3 प्रतिशत और फोकस प्रोडक्ट स्कीम (एफपीएस) और एमएलएफपीएस के लिए 1.25 प्रतिशत से 2 प्रतिशत और स्पेशल फोकस उत्पादों के लिए 5 प्रतिशत तक बढ़ाया गया।
- एफपीएस के अंतर्गत लगभग 135 मौजूदा उत्पादों, जिन्हें निर्यातों में मंदी के कारण हानि उठानी पड़ी है, के लिए 5 प्रतिशत/2 प्रतिशत के मौजूदा लाभों के अतिरिक्त 2 प्रतिशत बोनस का अतिरिक्त लाभ। प्रमुख सेक्टरों में शामिल हैं; सभी हस्तशिल्प मदें, रेशमी कालीन, खिलौने और खेलकूद की वस्तुएं (जिनमें सभी पहले 5 प्रतिशत लाभों के लिए पात्र थी); चमड़ा उत्पाद और चमड़ा फुटवियर, हथकरघा उत्पाद और साइकिल पुर्जों तथा ग्राइन्डिग मीडिया बाल्स सहित कुछ इंजीनियरिंग मदें (जिनमें सभी पहले 2 प्रतिशत लाभ की पात्र थीं)।
- एफपीएस के अंतर्गत 256 नए उत्पाद जोड़े गए (आठ अंकीय स्तर पर), जो सभी बाजारों के लिए एफओबी मूल्य के 2 प्रतिशत लाभों के पात्र थे। प्रमुख सेक्टर/उत्पाद समूह है-इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, रबर और रबर उत्पाद, अन्य ऑयल खाद्य पदार्थ, तैयार चमड़ा, पैकेज्ड नारियल पानी और नारियल के खोल से बनी मदें।
- इंस्टांट चाय और सीएसएनएल कार्डिनोल में विशेष कृषि ग्राम उपज योजना के अंतर्गत निर्यातों के एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) मूल्य का 5 प्रतिशत लाभ शामिल थे।
- एमएलएफपीएस के अंतर्गत रेडिमेड वस्त्र सेक्टर से लगभग 300 उत्पादों (आठ अंकीय स्तर पर) को 27 यूरोपीय संघ देशों को निर्यात के लिए अक्तूबर 2010 से मार्च 2011 तक आगे की छह माह की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया गया।

प्रौद्योगिकीय उन्नयन हेतु सहायता

- 2009 में सीमित सेक्टरों के लिए आरंभ की गई और आरंभ में केवल दो वर्ष के लिए वैध जीरों ड्यूटी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स (ईपीसीजी) स्कीम और स्टेट्स होल्डर इंसेटिव स्क्रिप (एसएचआईएस) स्कीम को एक और वर्ष 31 मार्च, 2012 तक बढ़ा दिया गया और योजना का लाभ अतिरिक्त क्षेत्रों तक पहुंचाया गया।
- तीन अतिरिक्त निर्यात उत्कृष्टता के शहरों की घोषणा की गई जिससे यह सूची 24 तक पहुंच गई।

रियायती निर्यात ऋण की उपलब्धता

- निर्यात के कतिपय श्रम प्रधान क्षेत्रों के लिए 2 प्रतिशत की ब्याज आर्थिक सहायता मार्च, 2011 तक बढ़ाई गई।
- फरवरी 2010 में विदेशी मुद्रा में निर्यात ऋण पर ब्याज दरें पहले की लिबोर + 350 बीपीएस से घटाकर लिबोर + 200 बीपीएस कर दी गई।

ईओयू/एसटीपीआई

- धारा 10क और 10ख (क्रमश: एसटीपीआई और ईओयू योजनाओं के लिए समापन खंड) का विस्तार वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए किया गया। 'यूनिट बनाम निर्धारिती' के कराधान लाभ से संबंधित धारा 10कक में विसंगति को हटा दिया गया।

सेवायें

- एफटीपी ने 'सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम' (एसएफआईएस) के तहत शुल्क रहित हकदारिता विदेशी मुद्रा अर्जन का दुगना 5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत करके सेवा क्षेत्र (होटल) को भी प्रोत्साहन प्रदान किया।

अन्य

- ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक (डीईपीबी) योजना का विस्तार 31 दिसम्बर 2010 से आगे 30 जून 2011 तक कर दिया गया।
- गैर-हैसियत धारक निर्यातकों के निर्यात को कार्यरूप देने की समयावधि बढ़ाकर, हैसियत धारकों के बराबर 12 माह कर दी गई। यह सुविधा 31 मार्च 2011 तक बढ़ा दी गई है।
- वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम प्राधिकार पर अब डंपिग रोधी और सेफगार्ड ड्यूटी के भुगतान से छूट दे दी गई है।
- वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क रहित आयात पर मूल्य सीमा 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है।
- डीईपीबी और मुक्त रूप से अंतरणीय प्रोत्साहन योजनाओं को अनन्तिम रूप से बैंक उगाही प्रमाणपत्र (बीआरसी) की प्राप्ति की प्रतीक्षा किए बिना अनुमति दी गई।
- संरचना शुल्क के भुगतान के बिना अग्रिम प्राधिकार योजना के अधीन निर्यात देनदारी अवधि 24 माह से बढ़ाकर 36 माह की गई।
- विभिन्न इलेक्ट्रोनिक डाटा इंटरचेंज कार्यक्रमों यथा ऑनलाइन फाइलिंग और विभिन्न प्राधिकारों की प्रोसेसिंग के माध्यम से व्यापार की सुविधा जिससे लेनदेन लागत और समय कम लगे।

सारणी 7.16 : शीर्ष 15 राज्यों का राज्यवार निर्यात

(मिलियन अमरीकी डालर)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2008-09	2009-10	(अप्रैल-सित.) 2009-10	(अप्रैल-सित.) 2010-11	शेयर 2009-10	वृद्धि दर (%) 2009-10	वृद्धि दर (%) 2010-11 (अप्रैल-सित.)
1.	महाराष्ट्र	44,661	43,351	20,275	23,405	24.3	-2.9	15.4
2.	गुजरात	40,268	38,771	16,341	24,593	21.7	-3.7	50.5
3.	तमिलनाडु	18,538	16,083	7899	8404	9.0	-13.2	6.4
4.	कर्नाटक	12,295	9092	4206	5011	5.1	-26.0	19.1
5.	आंध्र प्रदेश	9896	8558	4594	6620	4.8	-13.5	44.1
6.	केरल	4752	5842	2783	2647	3.3	22.9	-4.9
7.	हरियाणा	4791	5678	2653	3575	3.2	18.5	34.8
8.	उत्तर प्रदेश	7570	5523	2762	3848	3.1	-27.0	39.3
9.	दिल्ली	8466	5187	2575	2933	2.9	-38.7	13.9
10.	पश्चिम बंगाल	5582	4197	1826	2821	2.3	-24.8	54.5
11.	राजस्थान	3313	3338	1434	1853	1.9	0.8	29.2
12.	उड़ीसा	3351	3230	1233	2736	1.8	-3.6	121.9
13.	पंजाब	3015	2732	1260	1904	1.5	-9.4	51.1
14.	गोवा	1781	2481	557	1074	1.4	39.3	92.7
15.	मध्य प्रदेश	2945	2357	916	1147	1.3	-20.0	25.2
	भारत का कुल निर्यात	**1,85,295**	**1,78,751**	**80,950**	**1,05,352**	**100.0**	**-3.5**	**30.1**

स्रोत : डीजीसीआई एण्ड एस
*** वृद्धि दर अमरीकी डालर में**

गई है। अलग-अलग मिशन अभिनव निर्यात संवर्धन परियोजना प्रस्तावों को प्रस्तुत करके निधि से सहायता हेतु दावा प्रस्तुत करेंगे। प्राथमिकता, परिमात्रात्मक/सुस्पष्ट परिणामयुक्त केन्द्रित, विशिष्ट परियोजनाओं को दी जाएगी। 2010-11 के दौरान 31 दिसम्बर 2010 तक इस योजना के तहत कुल 205 परियोजनाओं/निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों और आठ बाजार अध्ययनों/निर्यात संवर्धन सर्वेक्षणों को सहायता हेतु मंजूरी दी गई।

7.54 देश के निर्यात व्यापार को प्रोत्साहित करने और उसमें विविधता लाने के लिए विपणन विकास सहायता योजना चलाई जा रही है। वर्ष 2010-11 के दौरान 31 दिसम्बर 2010 तक, कुल 411 परियोजनाओं/निर्यात संवर्धन कार्यक्रमों को सहायता के लिए अनुमोदित किया गया है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

7.55 भारत ने निर्यात के संवर्धन में निर्यात प्रोसेसिंग जोन (ईपीजेड) मॉडल की कारगरता को काफी पहले पहचान लिया था और 1965 में कांडला में एशिया के पहले ईपीजेड की स्थापना की गई थी। नियंत्रणों और स्वीकृतियों की बहुलता; विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और भारत में वृहत्तर विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक अस्थिर राजकोषीय व्यवस्था की कमी को दूर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की घोषणा की गई। भारत में एसईजेड 1 नवम्बर 2000 से 9 फरवरी 2006 तक विदेशी व्यापार नीति के उपबंधों के तहत कार्यरत थे और राजकोषीय प्रोत्साहन संबंधित कानूनों के उपबंधों के जरिए दिए गए। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005, एसईजेड कानूनों के साथ 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हुए। इनमें क्रियाविधियों का अत्याधिक सरलीकरण और केन्द्र तथा राज्य सरकारों से संबंधित मामलों पर एकल खिड़की मंजूरियों का प्रावधान किया गया। एसईजेड नियमों में एसईजेड की विभिन्न श्रेणियों के लिए विभिन्न न्यूनतम भूमि की आवश्यकताओं का प्रावधान है।

7.56 एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पूर्व गठित सात केन्द्र सरकार के एसईजेड और 12 राज्य/निजी क्षेत्र के एसईजेड के अतिरिक्त, 580 प्रस्तावों को औपचारिक अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसमें से 374 एसईजेड को अधिसूचित किया गया है। कुछ आलोचना के बावजूद एसईजेड का कार्यनिष्पादन पर्याप्त अच्छा रहा है। (देखें बॉक्स 7.4)

टैरिफ सुधार

7.57 वैश्विक मंदी ने टैरिफ सुधार प्रक्रिया की समीक्षा के लिए मजबूर किया। पिछले दो वर्षों में सबसे अधिक लगने वाले शुल्कों पर ठहराव लगाया गया जिसमें विनिर्मित वस्तुओं पर अधिकतम दर 10 प्रतिशत पर जारी है। टैरिफ में एकमात्र घट-बढ़ मुक्त

बॉक्स 7.4 : भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन

विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत के निर्यात में अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। एसईजेड का कार्यनिष्पादन मुख्य रूप से तीन क्षेत्रों में जांचा जाता है-निर्यात, रोजगार और निवेश

निर्यात: कुल 130 विशेष आर्थिक क्षेत्र पहले ही निर्यात कर रहे हैं। इनमें से 75 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/आईटी समर्थित सेवाएं, 16 बहुल उत्पाद और 39 अन्य सेक्टर विशिष्ट एसईजेड हैं। इन एसईजेड में यूनिटों की कुल संख्या 3139 हैं। एसईजेड से वास्तविक निर्यात 121 प्रतिशत बढ़कर 2009-10 में 2,20,711 करोड़ रुपए हो गया है जिसमें 2003-04 से 2009-10 के दौरान 58.6 प्रतिशत का सीएजीआर था, जिसकी तुलना में इसी अवधि में देश के कुल पण्य निर्यात के लिए सीएजीआर 19.3 प्रतिशत था। जब भारत सहित समूचा विश्व वैश्विक मंदी के प्रभावों से जूझ रहा था, एसईजेड से निर्यात में वृद्धि 2009-10 में 121 प्रतिशत थी जिसकी तुलना में भारत से कुल निर्यात में महज 0.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों के दौरान निर्यात 2,23,132.31 करोड़ रुपए हो गया है। भारत के कुल निर्यात में एसईजेड के हिस्से में निरन्तर वृद्धि हुई है। यह 2003-04 में 4.7 प्रतिशत से 2009-10 में 26.1 प्रतिशत और 2010-11 की पहली तीन तिमाहियों में 29. 7 प्रतिशत हो गया है (देखें सारणी 1)

सारणी 1 : एसईजेड का निर्यात और भारत का कुल निर्यात-एक तुलना

	एसईजेड से निर्यात		भारत से निर्यात		कुल निर्यात में एसईजेड के निर्यात का हिस्सा
	मूल्य (करोड़ ₹)	वृद्धि (%)	मूल्य (करोड़ ₹)	वृद्धि (%)	
2003-04	13,854	39.0	2,93,367		4.7
2004-05	18,314	32.2	3,75,340	27.9	4.9
2005-06	22,840	24.7	4,56,418	21.6	5.0
2006-07	34,615	51.6	5,71,779	25.3	6.1
2007-08	66,638	92.5	6,55,863	14.7	10.2
2008-09	99,689	49.6	8,40,755	28.2	11.9
2009-10	2,20,711	121.4	8,45,534	0.6	26.1
2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर)	2,23,132	-	7,51,633	23.4	29.7

एसईजेड की एक आलोचना इस बात के लिए होती है कि निर्यात मुख्य रूप से पुराने एसईजेड से हो रहा है जो पहले मुक्त व्यापार क्षेत्र (एफटीजेड) थे, न कि ग्रीनफील्ड एसईजेड से। यह जानना दिलचस्प होगा कि न केवल कई ग्रीनफील्ड एसईजेड ने निर्यात करना आरंभ कर दिया है, वरन नए एसईजेड अर्थात एसईजेड अधिनियम 2005 के अधीन अधिसूचित एसईजेड का निर्यात भी गत वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप एसईजेड अधिनियम 2005 से पूर्व स्थापित केन्द्र सरकार के एसईजेड और राज्य सरकार/निजी एसईजेड की तुलना में 2009-10 में इस श्रेणी का 53.4 प्रतिशत का सर्वाधिक हिस्सा रहा है। (देखें सारणी 2)

सारणी 2 : नए और पुराने विशेष आर्थिक क्षेत्रों से निर्यात

	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
केन्द्र सरकार के एसईजेड					
मूल्य (करोड़ रुपये में)	19,657	25,358	39,275	46,985	58,037
वृद्धि (%)	-	29	54.9	19.6	23.5
हिस्सा (%)	86.1	73.3	58.9	47.1	26.3
सेज अधिनियम 2005 से पूर्व स्थापित राज्य सरकार					
मूल्य (करोड़ रुपये में)	3183	9134	22,167	31,640	44,729
वृद्धि (%)	-	187	142.7	42.7	41.4
हिस्सा (%)	13.9	26.4	33.3	31.7	20.3
सेज अधिनियम, 2005 के अधीन अधिसूचित					
मूल्य (करोड़ रुपये में)	-	122	5195	21,064	1,17,946
वृद्धि (%)			4158.2	305.5	459.9
हिस्सा (%)	-	0.4	7.8	21.1	53.4

रोजगार: एसईजेड में 6,44,073 व्यक्तियों को कुल रोजगार में से, फरवरी 2006, जब सेज अधिनियम प्रवृत्त हुआ, के बाद 5,09,369 व्यक्तियों के लिए वृद्धिशील रोजगार सृजित हुआ। एसईजेड यूनिटों के प्रचालन के परिणामस्वरूप, एसईजेड से बाहर कम से कम इस संख्या का दुगना अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त करता है। यह अवसंरचना क्रियाकलापों हेतु डवलपर द्वारा सृजित रोजगार के अतिरिक्त है।

(जारी.....)

बॉक्स 7.4 : भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों का कार्यनिष्पादन (जारी....)

निवेश: 31 दिसम्बर 2010 तक एसईजेड में कुल निवेश लगभग 1,95,348 करोड़ रुपए है, जिसमें नव अधिसूचित क्षेत्रों में 1,91,313 करोड़ रुपए शामिल हैं। एसईजेड में, स्वत:मार्ग से शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। सरकार की भूमिका कोई प्रत्यक्ष मौद्रिक सहायता प्रदान करने की बजाय अनुमोदनों की फास्ट ट्रेकिंग करके सुविधा प्रदाता की है। एसईजेड अधिनियम 2005 के अधीन गठित किए जा रहे एसईजेड मुख्य रूप से निजी निवेश से संचालित हैं।

मुद्दे

एसईजेड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे निम्नलिखित हैं:

प्रत्यक्ष कर संहिता (डीटीसी) का प्रभाव: यह मुद्दा लाभ से जुड़ी कटौतियों के लिए अंतिम तारीखों से संबंधित हैं: डीटीसी के अनुसार, एसईजेड विकासकर्ताओं को 31 मार्च 2012 को या उससे पूर्व अधिसूचित सभी एसईजेड के लिए लाभ-सम्बद्ध कटौतियों की अनुमति दी जाएगी। एसईजेड में उन यूनिटों, जो 31मार्च 2014 तक वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ करेंगे, को भी लाभ-सम्बद्ध छूटों की अनुमति दी जाएगी। इन तारीखों के बाद अधिसूचित विकासकर्ताओं और यूनिटों को केवल निवेश सम्बद्ध छूटें मिलेंगी और लाभ-सम्बद्ध छूटें नहीं। इन तारीखों के बारे में विशेष रूप से बड़े एसईजेड डवलपरों और यूनिटों के बीच चिन्ता है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी): विचार किए जा रहे जीएसटी माडल के अनुसार, जीएसटी आवश्यक संवैधानिक संशोधनों सहित आयात पर लगाया जाएगा। यद्यपि, जीएसटी लागू होने के बाद, वस्तुओं और सेवाओं के आयात पर प्रदत्त जीएसटी पर पूर्ण प्रतिपूर्ति उपलब्ध होगी, यदि आवश्यक हो तो औद्योगिक प्रोत्साहनों से सम्बन्धित कर छूटों, पारेषणों आदि को कर के संग्रह के बाद नकदी वापसी योजनाओं में बदला जाना चाहिए, ताकि प्रतिपूर्तियों के निरंतर श्रृंखला के आधार पर जीएसटी योजना में व्यवधान न पड़े। विशेष औद्योगिक क्षेत्र योजनाओं के बारे में, ये छूटें, पारेषण केन्द्र और राज्य दोनों के लिए वैध समाप्ति के समय तक जारी रहेंगी, तथापि कोई नई छूट, पारेषण या पूर्ववर्ती छूट को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे मामलों में केन्द्र और राज्य सरकार जीएसटी संग्रहित करने के बाद प्रतिपूर्ति दे सकती है।

विद्युत उत्पादन और वितरण का मुद्दा: एक अन्य चिंता का विषय सेज विकासकर्ताओं, यूनिटों द्वारा विद्युत का उत्पादन और वितरण है। जहां एक मत यह है कि इसे निर्णय के लिए उद्यमी पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि क्या वह विद्युत को सेज अधिनियम में यथापरिभाषित अवसंरचना के रूप में उपलब्ध कराना चाहेगा अथवा विद्युत को एक वस्तु के रूप में बेचने के लिए यूनिट की स्थापना करेगा, एक अन्य विचार यह है कि विद्युत अवसंरचना नहीं हो सकती है और यह यूनिट द्वारा केवल उत्पादित की जाने वाली और वितरित की जाने वाली वस्तु ही हो सकती है यह एक उपयुक्त विचारणीय नीति हो सकती है।, जिसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

समन्वय से संबंधित मुद्दे: एसटीपीआई के निदेशकों को उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के अधीन आईटीएसईजेड के लिए विकास आयुक्त घोषित किया गया है। एक एसटीपीआई सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में है। अन्य बहु-उत्पाद और सेक्टर-विशिष्ट एसईजेड वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त डीसी के प्रभार में हैं। तथापि अनेक मुद्दे, उदाहरणार्थ आईटीएसईजेड की अधिसूचना की कार्रवाई, आईटीएसईजेड के संबंध में राज्य सरकारों के साथ समन्वय भी वाणिज्य विभाग द्वारा नियुक्त डीसी द्वारा देखे जाते हैं। इससे दोहरे नियंत्रण की स्थिति पैदा होती है जिससे प्रभावी समन्वय पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसका समाधान किए जाने की आवश्यकता है।

विनिवेश

नए एसईजेड मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में आए हैं जिनमें सरकार की कोई निधि नहीं लगी है। अब संभवत: समय आ गया है कि क्या कुछ राज्य के स्वामित्व वाले कुछ सुस्थापित एसईजेड का भी निजीकरण कर दिया जाए। इन एसईजेड के विनिवेश न केवल सरकार की आय में वृद्धि होगी और सामाजिक-क्षेत्र के विकास के लिए अधिक धन जारी किया जा सकता है, अपितु इन विशेष आर्थिक क्षेत्रों को अधिक कार्यक्षम भी बनाया जा सकता है।

व्यापार करारों के क्षेत्र में थी, जैसे कि अशियान में 2009-10 में टैरिफ नीति विशिष्ट मदों के आयात शुल्कों को कम करके मुद्रास्फीति को काबू में करने पर केन्द्रित थी। चालू खाता घाटे के संबंध में वर्तमान चिन्ताओं के कारण जहां यह रोक बनी रह सकती है, वहीं इस कठिन समय में भी टैरिफ सुधारों की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। (देखें बॉक्स 7.5)

7.58 अन्य टैरिफ सुधारों में ये उपाय शामिल हो सकते हैं–अंतिम प्रयोक्ता छूटों को कम करना क्योंकि 2009-10 में निर्यात संवर्धन रियायतों के कारण परित्यक्त राजस्व 43622 करोड़ रुपए था, प्रतिलोमित शुल्क ढांचे में सुधार करना, पेट्रोलियम उत्पादों से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाना क्योंकि प्रशासनिक मूल्य तंत्र समाप्त कर दिया गया है और टैरिफ रियायतों वाली निर्यात संवर्धन स्कीमों के लिए समापन खण्ड लागू करना।

अनुषंगी व्यापार नीति और टैरिफ-भिन्न उपाय

7.59 सभी देशों द्वारा शुरू किए गए डम्पिंग रोधी अन्वेषण 2001 में शिखर पर पहुंचने के बाद, गिरने आरंभ हुए और 2007 में इनकी संख्या 165 हो गई। तथापि 2008 में वे फिर बढ़कर 213 हो गए। 2009 में जहां इनकी संख्या मामूली रूप से 2009 तक गिरी, वहीं 2010 में इनमें काफी कमी दिखाई पड़ती है, जहां वर्ष के पूर्वार्द्ध में केवल 69 अन्वेषण आरंभ किए गए (सारणी 7.17)। भारत के डंपिंग-रोधी अन्वेषण 2008 में 55 से गिरकर 2009 में 31 हो गए। 2010 के पूर्वार्ध में, भारत द्वारा 17 डंपिंग रोधी अन्वेषण थे। 2010-11 के दौरान (31 दिसम्बर 2010 तक), डंपिंग रोधी और सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय ने 13 नए डंपिंग रोधी अन्वेषण आरंभ किए हैं। इसमें शामिल उत्पाद हैं-कतिपय हौट रोल्ड फ्लैट स्टनेलैस स्टील उत्पाद, एजोडिकाबोनामाइड, सिलाई मशीन की सुइयां, कास्टिक सोडा,

बॉक्स 7.5 : न्यूनतम राजस्व हानि के साथ अधिकतम शुल्कों में कमी करना

इस तथ्य को देखते हुए कि 2009-10 में कुल संग्रहण दरें (प्रतिकर और विशेष अतिरिक्त शुल्कों सहित शुल्कों के समग्र भार का संकेतक) 5.9 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई हैं (देखें सारणी 1), संग्रहण दरों में कोई गिरावट के बिना शुल्कों में बुद्धिमतापूर्वक सुधार करके विनिर्मित उत्पादों की अधिकतम दरों को कम किया जा सकता है। गिरते हुई संग्रहण दर बढ़ती हुई आयात की मात्रा तथा अंतिम प्रयोग आयातित वस्तुओं पर लागू प्रतिकर उत्पाद शुल्क के मद में छूटों के कारण कर वंचना दोनों का परिणाम है।

सारणी 1 : चुनिंदा आयात समूहों की संग्रहण दरें*

क्रं. सं.	वस्तु समूह	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
1	खाद्य उत्पाद	19.3	22	32.2	23.2	19.3	4.2	2.5
2	पीओएल	11.2	9.9	5.9	5.4	5.7	2.7	1.9
3	रसायन	24.1	21.6	20.1	22.1	21.6	16.4	13.9
4	मानव निर्मित फाइबर	45.9	38.7	33.6	28.3	30.1	17	22
5	कागज और अखबारी कागज	7.2	7.4	9.2	9.5	10.3	8.4	7.7
6	प्राकृतिक फाइबर	13	10.6	12.5	12.1	12.6	5.6	4.3
7	धातुएं	32	25.8	25	24.1	24.3	16.8	17.4
8	पूंजीगत वस्तुएं	19	15.8	12.5	14.3	15.7	12.5	11.3
9	अन्य	7.6	5.5	5.2	5.7	6.1	4	3.8
10	गैर पीओएल	14.4	12.1	11.5	12.3	12.8	8.7	7.6
	कुल	**13.5**	**11.5**	**9.8**	**10.2**	**10.4**	**6.9**	**5.9**

स्रोत : राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय

*संग्रहण दर को राजस्व संग्रहण (बुनियादी सीमा शुल्क + प्रतिकर शुल्क) का आयात का मूल्य के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें छूटों का समायोजन नहीं है। इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

क्र.सं. 1 में अनाज, दालें, चाय, दूध और क्रीम, फल, सब्जियां, पशुओं की चर्बी और चीनी शामिल है।

क्र.सं. 3 में रासायनिक तत्व, यौगिक पदार्थ, फार्मास्यूटिकल, डाई करने और रंगाई की सामग्री, प्लास्टिक और रबर शामिल है।

क्र.सं. 5 में लुगदी और रद्दी कागज़ न्यूजप्रिंट पेपर बोर्ड और विनिर्माण तथा मुद्रित पुस्तकें शामिल हैं।

क्र.सं. 6 में कच्चा ऊन और रेशम शामिल है।

क्र.सं. 7 में लोहा और इस्पात तथा गैर अयस्क धातुएं शामिल हैं।

क्र.सं. 8 में गैर इलेक्ट्रोनिक मशीनरी तथा परियोजना आयात, विद्युत मशीनरी शामिल है।

2009-10 में, पूंजीगत वस्तुओं के अंतर्गत 340 टैरिफ लाइनें और मध्यवर्ती वस्तुओं, जिनमें मुख्य रूप से तैयार शुदा उत्पादों के विनिर्माण में काम आने वाली वस्तुएं हैं जिन पर 10 प्रतिशत या अधिक शुल्क लगता है, के अंतर्गत 4135 लाइनें हैं। उच्च शुल्क श्रेणी में दो समूह टैरिफ लाइनों की कुल संख्या का लगभग 39 प्रतिशत हैं। धारणात्मक शुल्क (अर्थात् वह राजस्व जो यदि अंतिम प्रयोक्ता छूट अथवा निर्यात संवर्धन जैसी विशेष श्रेणी न होती तो आयात की मात्रा से राजकोष में प्राप्त हुआ होता) में 10 प्रतिशत और उससे अधिक के शुल्क स्लैब में दो श्रेणियों का हिस्सा 2,02,705 करोड़ रुपए अनुमानित कुल धारणात्मक राजस्व का 2.5 प्रतिशत (पूंजीगत वस्तुओं के मामले में) और 33.5 प्रतिशत (मध्यवर्ती वस्तुओं के मामले में) है। यदि पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं दोनों को 7.5 प्रतिशत शुल्क स्लैब में लाया जाता है और यदि संग्रहण दरें समान मान ली जाएं, तब लगभग 11747 करोड़ रुपए की राजस्व हानि है। तथापि मध्यवर्ती और पूंजीगत वस्तुओं के मामले में संग्रहण दरें 10 प्रतिशत और अधिक स्लैब की तुलना में 7.5 प्रतिशत शुल्क स्लैब में उच्चतर हैं। यदि संग्रहण दरों को गणना में लिया जाए, तो बेहतर कर अनुपालन और 10 प्रतिशत से अधिक स्लैब की तुलना में कम शुल्क 7.5 प्रतिशत के स्लैब में सुधरी हुई संग्रहण दर से जुड़े अल्प मूल्यांकन में कमी के कारण राजस्व में वास्तविक उपलब्धि हो सकती है। इसका एक कारण यह है कि प्रतिकर शुल्क छूटें, उदाहरणार्थ टेक्सटाइल में, 7.5 प्रतिशत स्लैब की तुलना में 10 प्रतिशत के स्लैब में व्यापक रूप से फैली हैं।

पूंजीगत और मध्यवर्ती वस्तुओं को 7.5 प्रतिशत के स्लैब में डालने के परिणामस्वरूप 7.5 प्रतिशत शुल्क के टैरिफ लाइनों की संख्या कुल का 79.6 प्रतिशत (अथवा लगभग 80 प्रतिशत) हो जाएगी। उनमें आयात का 97.45 प्रतिशत आ जाएगा। भले ही कुछ मध्यवर्ती और सभी पूंजीगत वस्तुओं को 7.5 प्रतिशत या उससे नीचे की श्रेणी में डाल दिया जाए तो विनिर्माण के अधिकांश भाग की अधिकतम शुल्क दर 7.5 प्रतिशत या कम होगी। औद्योगिक वृद्धि और निर्यात को इससे बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और इससे डब्ल्यूटीओ वार्ता और एफटीओ में अपना पक्ष मजबूती से रखा जा सकेगा।

सारणी 1यह भी दर्शाती है कि पूंजीगत वस्तुओं के लिए संग्रहण दरें निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु योजना के अंतर्गत रियायतों सहित सभी छूटों के बाद 11.3 प्रतिशत पर अभी भी अपेक्षाकृत उच्च है। इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है।

सारणी 7.17 : डंपिंग रोधी उपायों के शीर्ष दस प्रयोक्ताओं द्वारा शुरू किए गए अन्वेषण 1995-2008

देश	1995	2000	2001	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010*	1995-2010*
भारत	6	41	79	21	28	35	47	55	31	17	613
यूनाइटेड स्टेट	14	47	77	26	12	8	28	16	20	2	442
यूरोपियन समुदाय	33	32	28	30	25	35	9	19	15	8	414
अर्जेन्टायिना	27	43	28	12	12	11	8	19	28	7	277
दक्षिण अफ्रीका	16	21	6	6	23	3	5	3	3	0	212
आस्ट्रेलिया	5	15	23	9	7	10	2	6	9	4	212
ब्राजील	5	11	17	8	6	12	13	23	9	5	184
कनाडा	11	21	25	11	1	7	1	3	6	1	152
रिपब्लिक चीन	0	11	14	27	24	10	4	14	17	4	182
टर्की	0	7	15	25	12	8	6	23	6	1	145
सभी देश	157	298	371	220	202	203	165	213	209	69	3752

स्रोतः डब्ल्यूटीओ *जून 2010 तक

पैरानिट्रोआनिलाइन, 600 मिमी. से कम चौड़ाई के 200 सीरीज के स्टेनलैस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, 600 मिमी. से कम चौड़ाई के 400 सीरीज के स्टेनलैस स्टील कोल्ड रोल्ड फ्लैट उत्पाद, सोडा एश, ओपल ग्लासवेयर, मेलामाइन, मोरफोलाइन, जियोग्रिड और एनिलाइन-III। इन अन्वेषणों में संलिप्त देश हैं-यूरोपीय संघ, कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, ताइवान, यूएसए, चीन लोक गणराज्य, थाइलैण्ड, नोर्वे, यूएई, कीनिया, इरान, पाकिस्तान, तुर्की, यूक्रेन, इंडोनेशिया जापान, मलेशिया।

7.60 पिछले दो दशकों के दौरान विश्व में वैश्विक व्यापार का तेजी से विस्तार और डब्ल्यूटीओ के अधीन बहुपक्षीय प्रबन्ध तथा एफटीए सहित व्यापार सहयोग के विभिन्न प्रकारों दोनों के माध्यम से टैरिफ दरों में कटौती देखी गई। तथापि, इसके साथ ही विकसित देश अपने घरेलू उद्योगों को संरक्षित करने के लिए गैर-टैरिफ उपायों के प्रयोग का अधिकाधिक सहारा ले रहे हैं।

7.61 जी-20 व्यापार और निवेश उपायों के संबंध में डब्ल्यूटीओ-अंकटाड (संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन)-ओईसीडी-रिपोर्टों (जिसमें चौथी रिपोर्ट अद्यतन है) में कहा गया है कि जी-20 देशों द्वारा लगाए गए नए उपायों की संख्या अभी भी बढ़ रही है, परन्तु यह विगत की अपेक्षा अधिक धीमी गति से है और नए व्यापार उपचारात्मक कार्रवाइयों (डंपिंग रोधी शुल्क, प्रतिकर उपाय और सुरक्षोपाय) में स्वागतयोग्य गिरावट है। वैश्विक मंदी के बाद विभिन्न अवधियों के दौरान शुरु किए गए नए प्रतिबंधात्मक उपायों में गिरावट दिखती है, जिसमें मई 2010-अक्तूबर 2010 में कुल जी-20 आयात का केवल 0. 3 प्रतिशत और विश्व आयात का 0.2 प्रतिशत शामिल है। (देखें सारणी 7.18)

7.62 तथापि, व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों में बढ़ोत्तरी हो रही है और उन्हें दूर करने में सीमित प्रगति हो रही है। अक्तूबर 2008 से, कुल मिलाकर, नए जी-20 व्यापार प्रतिबन्ध बढ़कर जी-20 आयात का 1.8 प्रतिशत और कुल विश्व आयात का 1. 4 प्रतिशत कवर करते हैं। संकट के प्रदुर्भाव के बाद शुरू किए गए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों का अब तक केवल लगभग 15 प्रतिशत को ही हटाया गया है, जो दर्शाता है कि उनमें से अधिकांश अभी भी प्रवर्तन में हैं।

7.63 व्यापार उपायों की संख्या की दृष्टि से, सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत मशीनरी और उपकरण; रासायनिक उत्पाद; खनिज ईंधन; मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, लोहा और इस्पात; अनाज, प्लास्टिक उत्पाद और दुग्ध उत्पाद शामिल हैं। प्रतिबंधात्मक उपायों की व्यापार कवरेज की दृष्टि से सबसे अधिक प्रभावित सेक्टर थे-लाइन टेलीफोनी के लिए विद्युत उपस्कर, बायोडीजल और स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीनें। मध्य-मई 2010 के बाद जी-20 कार्रवाइयों का अधिकांश हिस्सा व्यापार संबंधी उपचार रहे हैं- विशेष रूप से नए डंपिंग-रोधी अन्वेषणों की शुरूआत, जिसके बाद टैरिफों और अन्य आयात-संबंधित करों में

सारणी 7.18 : नए व्यापार प्रतिबंधात्मक उपायों का हिस्सा

	अक्तू. 2008–अक्तू. 2009	नवम्बर 2009–मई 2010	मई 2010–अक्तू. 2010
कुल विश्व आयात में	0.8	0.4	0.2
कुल पी-20 आयात में	1.0	0.5	0.3

वृद्धि/अप्रमाणित उपायों में, सर्वाधिक दुहराई जाने वाली कार्रवाइयां निर्यात करों या प्रतिबन्धों, गैर-टैरिफ उपायों (आयात-प्रतिबन्ध, लाइसेंस अथवा अन्य सीमावर्ती नियन्त्रण) तथा घरेलू उद्योगों या उत्पादों का पक्ष लेने के उद्देश्य से किए गए सरकारी उपायों से सम्बन्धित थे। सर्वाधिक दुहराए जाने वाले निर्यात उपाय कुछ कृषि उत्पादों पर प्रतिबन्ध (निर्यात प्रतिबंध और अनाज को प्रभावित करने वाले कोटा) और कुछ खनिजों (निर्यात कोटा कटौतियां और विरले भूखनिजों पर कथित अनौपचारिक प्रतिबंध) से संबंधित थे।

7.64 कुछ जी-20 देशों ने टैरिफों में वृद्धि की है और कतिपय सेक्टरों, विशेषकर इस्पात और मोटर वाहनों में घरेलू उत्पादन को संरक्षित करने के लिए नए गैर-टैरिफ उपाय शुरू किए हैं। जी-20 देशों ने इन तथा अन्य सेक्टरों जैसे गैर-स्वचालित आयात लाइसेंसों जैसे अन्य सेक्टरों में व्यापार रक्षा तंत्रों का प्रयोग करना जारी रखा है। अमरीका और यूरोपीय संघ ने दुग्ध क्षेत्र के लिए कृषि निर्यात सब्सिडियां पुनः आरंभ की हैं। इन उपायों को सामान्यतया व्यापार में सर्वाधिक व्यवधानकारी उपाय माना जाता है। संकट से निबटने के लिए शुरू किए गए कुछ राजकोषीय और वित्तीय पैकेजों में कुछ ऐसे तत्व समाहित हैं जैसे राज्य सहायता, अन्य सब्सिडियां तथा 'स्थानीय/खरीदें/उधार दें/निवेश करें/किराए पर दें' जैसी शर्तें जो आयात के स्थान पर घरेलू वस्तुओं और सेवाओं का पक्ष लेती हैं। सेनिटरी और फिटोसेनिटरी (एसपीएस) उपाय और टीजीटी (व्यापार के प्रति तकनीकी अवरोध) विनियम और धीमी प्रक्रियाएं और अतिरिक्त प्रक्रियागत अपेक्षाएं देशों द्वारा लगाए गए अन्य उपाय हैं। इस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में, संकट की शुरूआत के बाद से नीतिगत पिछड़ापन रहा है और अप्रैल 2009 में जी-20 लंदन शिखर वार्ता के बाद भी यह जारी है।

7.65 भारत ने गैर-टैरिफ उपायों से संबंधित मुद्दों से निबटने के लिए बहु-मुखी रणनीति अपनाई है। निर्यात के पक्ष में सदस्यों द्वारा डब्ल्यूटीओ को एसपीएस और टीबीटी अधिसूचना (जिसका परिणाम एनटीएम हो सकता है) के संबंध में एक ऑन-लाइन डाटाबेस स्थापित किया गया है। यह निर्यातकों को अन्य देशों के विनियामक व्यवस्था के बारे में सूचना देने के लिए है। इसके अतिरिक्त, हमारे मानकों और विनियमों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पत्तनों और हवाई अड्डों पर अवसंरचना और निगरानी प्रणाली को उन्नत करने के कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त जहां कहीं भारत का निर्यात हित प्रभावित होता है, सरकार द्वारा एसपीएस और टीबीटी समिति जैसे डब्ल्यूटीओ के अधीन उपलब्ध उपयुक्त निवारक मंचों पर मुद्दे उठाए जाते हैं। इन मुद्दों को द्विपक्षीय मंचों पर भी उठाया जाता है।

डब्ल्यूटीओ वार्ता और भारत

व्यापार वार्ताएं

7.66 विश्व व्यापार संगठन में दोहा दौर की व्यापार वार्ताएं 2001 से चल रही हैं। दिसम्बर 2008 में, इनमें रुकावट आने के बाद वार्ता पुनः शुरु होने की प्रगति धीमी थी और तब से इसमें अधिक प्रगति नहीं हुई है। मार्च 2010 में डब्ल्यूटीओ में वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर स्थिति का जायजा लेने की कवायद शुरु हुई। इसमें सदस्य इस बात पर सहमत थे कि पहले ही किए जा चुके कार्य के आधार पर वार्ताओं को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही इस दौर के विकास आयाम पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखा गया। नवम्बर, 2010 में, सियोल में आयोजित जी-20 नेताओं की शिखरवार्ता में विश्व के नेताओं द्वारा दिए गए सकारात्मक संकेतों ने सदस्य देशों में जेनेवा प्रक्रिया जिसे जनवरी 2011 में पुनः आरम्भ होना था, के बारे में तात्कालिकता का बोध कराया है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने वार्ताओं के एक मिश्रित दृष्टिकोण, जिसमें विशिष्ट क्षेत्रों और क्षैतिजस्थ स्तर दोनों में वार्ताकारी समूह और द्विपक्षीय सम्पर्कों के भीतर अध्यक्ष के नेतृत्व में होने वाली प्रक्रियाओं को मिश्रित करने का रास्ता सुझाया है। भारत दोहा दौर के शीघ्र समापन की दिशा में डब्ल्यूटीओ में सहयोगी समूह के साथ कार्य करने का इच्छुक है। तथापि, इसका दृष्टिकोण बिल्कुल सुस्पष्ट है: विकासशील देशों के निर्धनों, आजीविका के लिए संघर्षरत किसानों और संवेदनशील उद्योगों का संरक्षण एक प्राथमिकता है।

7.67 कृषि के क्षेत्र में, 6 दिसम्बर, 2008 के संशोधित प्रारूप कृषि रूपात्मकता के पाठ के आधार पर वार्ताएं अभी चल रही हैं। इस प्रारूप के अनुसार विकसित देशों को अपने प्रतिबद्ध टैरिफों को पांच वर्ष की अवधि में 54 प्रतिशत की समग्र न्यूनतम औसत कटौती के साथ समान वार्षिक किस्तों में घटाना होगा। विकासशील देशों के अपने प्रतिबद्ध टैरिफों को दस वर्ष की अधिक लम्बी कार्यावधि के दौरान 36 प्रतिशत की अधिकतम समग्र औसत कटौती के साथ घटाना होगा। विकसित और विकासशील दोनों सदस्य देशों के पास ऐसी संवेदनशील उत्पादों के रूप में जिन पर वे कम टैरिफ कटौतियां करेंगे, उपयुक्त संख्या में टैरिफ लाइने निर्दिष्ट करने का लचीलापन होगा। विकासशील देशों के पास कृषि टैरिफ लाइनों के 12 प्रतिशत की एक विशेष उत्पाद हकधारिता होगी। शून्य कटौतियों पर कुल टैरिफों के 5 प्रतिशत सहित विशेष उत्पादों पर 11 प्रतिशत की एक औसत टैरिफ कटौती का प्रस्ताव है। घरेलू और निर्यात सब्सिडियों के विभिन्न श्रेणियों के लिए भी कटौतियों/सीमाओं का प्रस्ताव है।

7.68 कृषि-भिन्न बाजार पहुंच (एनएएमए) वार्ताओं के मामले में, विकासशील देशों के संवेदनशील (एनएएमए) टैरिफ लाइनों को संरक्षित करने हेतु विशिष्ट नम्यताओं से संबद्ध फार्मूला

कटौतियों हेतु 20,22 और 25 के त्रि-स्तरीय गुणांक और विकसित देशों की टैरिफ कटौती हेतु आठ के गुणांक वाले एक गैर रैखिक स्विस फार्मूला के माध्यम से टैरिफ कटौतियों का प्रस्ताव है। कुछ देशों के सेक्टर वार प्रस्ताव जिसके द्वारा कुछ चिहिन्त सेक्टरों में टैरिफों को शून्य या लगभग शून्य स्तरों पर लाने का प्रस्ताव है, के संबंध में भारत की वार्ता संबंधी स्थिति यह है कि सेक्टरवार कार्यक्रमों में भागीदारी अनिवार्य नहीं होनी चाहिए और यह परिणाम के पूर्वानुमान के बिना सदभावना आधार पर होनी चाहिए। एनएएमए वार्ताओं का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू गैर-टैरिफ अवरोधों से संबंधित है। इसके संबंध में भारत हॉरीजॉनटल मेकानिज्म (एचएम) प्रस्ताव के प्रारंभिक प्रवर्तकों में एक है। इसका उद्देश्य 'एनटीबी' को सुविधाजनक बनाने की प्रक्रियाओं के संबंध में मंत्री-स्तरीय निर्णय को अमल में लाना है। इस प्रस्ताव को एक सौ से अधिक डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त है। यद्यपि, दोहा का अधिदेश 6 विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के संदर्भ में एनटीबी से संबंधित है, सं.रा. अमरीका के नेतृत्व में कुछ देशों द्वारा पुनर्विनिर्मित वस्तुओं की इस बढ़ती बाजार पहुंच का इस्तेमाल करने के कुछ प्रयास हुए हैं। इस पर भारत की वार्ताकारी स्थिति यह है कि चूंकि पुनर्विनिर्मित वस्तुओं के संबंध में कोई सर्वसहमत परिभाषा नहीं है, अत: अन्य सेकेण्ड हैण्ड वस्तुओं जिनका विकासशील देशों के पर्यावरण और आजीविका के पहलुओं पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं, के विपरीत पुनर्विनिर्मित वस्तुओं को परिभाषित करने और उनमें अन्तर करने के लिए सबसे पहले एक कार्य योजना की आवश्यकता है। इस कार्य योजना को अब लगभग 17 देशों का समर्थन प्राप्त है।

7.69 सेवाओं में भारत एक मांगकर्ता देश रहा है। इसने अपनी प्रारंभिक पेशकश (जनवरी, 2004) तथा चल रही सेवा वार्ताओं के प्रथम संशोधित पेशकश (अगस्त, 2005) में पर्याप्त सेक्टरवार और रूपात्मक कवरेज प्रस्तुत की है। लघु मंत्री स्तरीय बैठक के साथ-साथ आयोजित सिंगनलिंग कॉन्फ्रेंस (जुलाई, 2008) में कुछ और सुधार भी बताए गए। तथापि, भारत की पेशकश/संकेत इसके मोड 1/2 और मोड 4 अनुरोधों के संबंध में संतुष्टि मिलने की शर्त पर हैं।

7.70 डब्ल्यूटीओ में सेवा संबंधी वार्ताओं में जी-20 बैठक के बाद फिर नई जान आई है। सभी सदस्यों द्वारा वार्ताओं की परिणति के लिए समिति अवसरों का लाभ उठाने हेतु वार्ताओं में तेजी लाने के प्रति रुचि व्यक्त की गई है। बहुपक्षीय प्रक्रिया, (जहां दो से अधिक देश शामिल हैं) के भाग के रूप में सेवा क्षेत्रों/प्रणालियों में डब्ल्यूटीओ में 22 बहुपक्षीय समूह गठित किए गए हैं। भारत मोड 1 (सीमा आर-पार आपूर्ति) और मोड IV (जन्मजात व्यक्तियों की आवाजाही), जो सेवा वार्ताओं में इसके हित का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, में बहुपक्षीय अनुरोधों का समन्वय करता है। भारत कम्प्यूटर और संबंधित सेवाओं और वास्तुशिल्प, इंजीनियरिंग और एकीकृत इंजीनियरिंग सेवाओं में बहुपक्षीय अनुरोधों का सह-प्रायोजक भी है।

7.71 भारत ने उरुग्वे दौर की प्रतिबद्धताओं से संबंधित पेशकशों पर काफी अधिक लचीलापन दर्शाया है; तथापि, मोड 1 और मोड 4 में इसके प्रारंभिक अनुरोधों पर प्रमुख विकसित देशों द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है। कुछ प्रमुख विकसित सदस्य देशों ने उनके मोड 4 पेशकशों में बहुत कम या कोई लचीलापन नहीं दर्शाया है जो भारत के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय है। अमरीका और आस्ट्रेलिया जैसे अन्य विकसित देश कार्यक्रम के समूहीकरण के रूप में सेवा वार्ताओं के प्रति नया दृष्टिकोण लाने का प्रयास कर रहे है। भारत ने प्रक्रियागत तथा मूलभूत आधारों पर समूहीकरण दृष्टिकोण का विरोध किया है। दोहा दौर के अंतर्गत सेवाओं में प्रगति की कमी वार्ताओं के दृष्टिकोण की समस्याओं के कारण ही नहीं है वरन् यह राजनीति इच्छा की कमी, विकासशील देशों के निर्यातों के सेक्टरों और क्षेत्रों में विकसित देशों का पर्याप्त रूझान और कृषि एनएएमए में कम लचीलापन है।

7.72 भारत के लिए निर्णायक हित का एक क्षेत्र, घरेलू विनियंत्रणों जिनमें योग्यता और लाइसेंसिंग अपेक्षाएं शामिल हैं, में विधाओं का विकास है जिसके बिना मोड 4 पहुंच गंभीर रूप से बाधित होती है। इस विषय पर वार्ताएं मार्च 2009 के अध्यक्ष के पाठ के आधार पर चल रही हैं। वार्ताओं को आगे ले जाने के उद्देश्य से सदस्य देशों द्वारा डब्ल्यूटीओ में पेशकशों का नया दौर लाने की आवश्यकता होगी। सेवाओं में दूसरी संशोधित पेशकशों को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा का निर्धारण कृषि और एनएएमए में प्राप्त समाधान के बाद किया जाएगा। सेवाओं में कोई महत्वकांक्षी परिणाम किसी समाधान पैकेज का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। भारत ने बार-बार यह कहा है कि सेवाओं में कोई भावी कार्य हांगकांग मंत्री-स्तरीय घोषणा के अनुबंध ग के अनुरूप होना चाहिए। सदस्यों को स्पष्ट रूप से यह बताने की आवश्यकता है कि वे अनुबंध-ग में वर्णित रूपात्मकता उद्देश्यों को किस तरह पूरा करना चाहते हैं विशेषरूप से विकसित देशों के हित के सेक्टरों और प्रणालियों में विशेषरूप से मोड 1 और मोड 4 में बाजार को खोलने के स्पष्ट संकेत देने होंगे।

नियमों संबंधी वार्ताएं

7.73 नियमों के संबंध में वार्ताकारी समूह में वार्ताएं हो रही हैं जिनका उद्देश्य डम्पिंग रोधी करार और सब्सिडी और प्रतिकर उपाय संबंधी करार (एएससीएम) के अधीन विषयों को स्पष्ट करना है, साथ ही मूल अवधारणाओं, सिद्धांतों तथा इन करारों और उनके साधनों और उद्देश्यों की कारगरता को परिरक्षित करना है। सदस्य मत्स्य सब्सिडियों के लिए नए विषयों पर भी चर्चा कर रहे हैं।

7.74 18 दिसम्बर 2008 के अध्यक्ष के प्रारूप पाठ पर चर्चाएं 2010 के दौरान जारी रहीं। डपिंग-रोध में शून्यीकरण, समापन पुनरीक्षाएं, न्यूनतर शुल्क नियम, लोकहित, हेतुत्व और परिवंचना-रोधी जैसे वृहत्तर मुद्दों पर सर्वसम्मति नहीं बन पाई है। सब्सिडी करार में, विनिर्दिष्टता, नियंत्रित मूल्यों पर उपलब्ध कराई गई निविष्टियों के मामले में सब्सिडियों और निर्यात वित्त के लिए बैंचमार्क संबन्धी प्रस्तावों पर काफी अधिक विभिन्नता रहती है। भारत डंपिंग रोधी नियमों के सुदृढ़ीकरण, ताकि डंपिंग मार्जिन परिकलन में शून्यीकरण के प्रयोग को रोका जा सके, समापन पुनरीक्षाओं के संचालन के लिए नियमों के सुदृढ़ीकरण और निम्नतर शुल्क के अनिवार्य प्रयोग की मांग करता रहा है। सब्सिडी करार में, भारत विकासशील देशों में एएससीएम में प्रतिबन्धित सब्सिडियों के दायरे के विस्तारीकरण और/अथवा मौजूदा नम्यताओं को सीमित करने का विरोध करता है। मात्स्यिकी सब्सिडियों संबंधी नए विषयों पर वार्ताओं पर भारत विकासशील देशों के लिए, विशेषकर लघु, शिल्पकार समुदायों के लिए रोजगार और आजीविका तथा पर्याप्त 'नीतिगत गुंजाइश' बनाए रखने, ताकि यह अपना बुनियादी ढांचा विकसित कर सकें, के परिप्रेक्ष्य में प्रभावी विशेष और विभेदक (एस एंड डी) व्यवहार की मांग कर रहा है।

व्यापार सुगमीकरण

7.75 दौहा दौर का एक अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र व्यापार सुगमीकरण संबंधी वार्ताएं हैं। व्यापारिक लागतों को कम करके व्यापार प्रक्रियाओं का सरलीकरण सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के हित में है। व्यापार सुगमीकरण के संबंध में डब्ल्यूटीओ सदस्यों द्वारा एक प्रारूप समेकित वार्ताकारी पाठ 14 दिसम्बर 2009 को तैयार किया गया। प्रारूप पाठ को तब से 2010 में व्यापार सुगमीकरण संबंधी वार्ताकारी समूह की बैठकों में चर्चाओं के जरिए छह बार संशोधित किया गया है। भारत इन बैठकों में सक्रिय रूप से भागीदारी कर रहा है और उसने 'सीमाशुल्क सहयोग', 'कस्टम यूनियन की तीव्र चेतावनी प्रणालियों' और 'अपील तंत्र' के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। विकसित देश अपनी व्यापार संबंधी क्रियाविधियों को बदलना नहीं चाहते हैं परन्तु अन्य से ऐसी अपेक्षा करते हैं। विकासशील देशों ने कुल मिलाकर वार्ताओं के प्रति अतिरिक्त सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाया है। सबसे कम विकसित देश, आमतौर पर, कोई बाध्यकारी प्रतिबद्धतता नहीं अपनाना चाहते हैं। क्षमता बाध्यताएं और संसाधनों की कमी दो प्रमुख कारक हैं जो विकासशील देशों (और सबसे कम विकसित देशों) को व्यापार सुगमीकरण में बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को लेने से रोकते हैं। वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि विकसित देश और अन्य दाता इन देशों में भौतिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश नहीं कर सकते हैं, यद्यपि जुलाई 2004 के फ्रेमवर्क करार में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए समर्थन करने और सहायता देने की प्रतिबद्धताओं को स्पष्ट रूप से जोड़ा गया है। यह महत्वपूर्ण है कि इस जुड़ाव का सभी डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों विशेषरूप से विकसित देशों द्वारा सम्मान किया जाए और प्रतिबद्धताओं के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान की जाए जिससे कि व्यापार सुगमीकरण संबंधी उच्च मानक करार पर पहुंचा जा सके।

द्विपक्षीय और क्षेत्रीय सहयोग

7.76 विगत में भारत ने क्षेत्रीयवाद के प्रति अत्यन्त सावधानीपूर्ण और सुरक्षित दृष्टिकोण अपनाया था। तथापि, इस बात को मानते हुए कि क्षेत्रीय और तरजीही कारोबारी करार विश्व व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे और बहुपक्षीय वार्ताओं की धीमी प्रकृत्ति को देखते हुए, भारत ने अधिकांशः मामलों में व्यापक आर्थिक सहयोग करारों की ओर बढ़ना आरम्भ किया, प्रमुख एफटीए/आरटीए/सीईसीए से संबंधित हाल के घटनाक्रम निम्नलिखित हैं:

- **भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और निवेश करार वार्ताएं:** भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक व्यापक आधारयुक्त द्विपक्षीय व्यापार और निवेश करार हेतु वार्ताएं जून 2007 में आरंभ हुईं। अब तक ग्यारह दौरों का आयोजन किया जा चुका है। अंतिम दौर जनवरी 2011 में भारत में आयोजित किया गया।

- **भारत-जापान आर्थिक साझेदारी करार (ईपीए) व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी करार (सीईपीए) वार्ताएं:** एक व्यापक आर्थिक सहयोग साझेदारी करार (सीईपीए) हेतु वार्ताएं जनवरी 2007 में शुरू की गई और 9 सितम्बर 2010 को टोक्यो में 14वें दौर के दौरान 'सिद्धान्तः' करार पर हस्ताक्षर किए गए।

- **भारत-मलेशिया व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए):** भारत-मलेशिया सीईसीए वार्ताएं फरवरी, 2008 में आयोजित की गईं। वार्ताओं का समापन सितम्बर, 2010 को हुआ। सीईसीए में वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्र शामिल हैं इसे एक एकल वचनपत्र के रूप में हस्ताक्षरित किया जाएगा। भारत-आसियान व्यापार को ध्यान में रखते हुए जिसे भारत और मलेशिया के बीच जनवरी 2010 में क्रियान्वित किया गया, दोनों पक्षों ने वस्तुओं में बाजार पहुंच पर 'आसियन प्लस' की पेशकश की है। 27 अक्तूबर, 2010 को भारत और मलेशिया के प्रधान मंत्रियों ने वार्ताओं के समापन की घोषणा की। 2011 के आरंभ तक इस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह 1 जुलाई 2011 तक क्रियान्वित किया जाएगा।

- **भारत-कोरिया सीईपीए:** भारत-कोरिया सीईपीए पर हस्ताक्षर 6 अगस्त, 2009 को किए गए और 1 जनवरी 2010 से क्रियान्वित किया गया जिसमें माल व्यापार निवेश, और सेवाओं और साझा हित के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग शामिल है। सीईपीए के अंतर्गत, कोरिया की टैरिफ लाइनों के 93 प्रतिशत तथा भारत की टैरिफ लाइनों के 85 प्रतिशत पर टैरिफ कम किया जाएगा या समाप्त किया जाएगा। इससे दोनों देशों द्वारा स्वतंत्र व्यावसायिकों एवं संविदात्मक सेवा प्रदाताओं की आवाजाही को सरल बनाने के लिए की गई अतिरिक्त प्रतिबद्धताओं के माध्यम से यह करार सेवाओं में व्यापार को सुविधाजनक बनाया जाएगा।
- **भारत-आसियान वस्तु व्यापार करार:** भारत और आसियान जिसमें ब्रुनई, दारूस्सलाम, कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं, के बीच 13 अगस्त, 2009 को एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) के वृहत्तर फ्रेमवर्क के अंतर्गत माल व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए गए। माल व्यापार करार में टैरिफ लाइनों के 80 प्रतिशत पर, जो व्यापार का 75 प्रतिशत बनता है, 1 जनवरी 2010 से आरंभ करके क्रमिक रूप से बुनियादी कस्टम ड्यूटी समाप्त करने का प्रावधान है। भारत ने कृषि, वस्त्र, ऑटो, रसायनों, अपरिष्कृत और परिष्कृत पाम तेल, कॉफी, चाय, गोल मिर्च आदि की संवेदनशीलताओं के निराकरण के लिए टैरिफ रियायतों की सूची से 489 एचएस 6 अंकीय लाइनों और टैरिफ समाप्तियों की सूची से 590 एचएस 6 अंकीय लाइनों को हटा दिया है।
- **एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए):** एपीटीए में बंगलादेश, कोरिया गणतंत्र, श्रीलंका, चीन, लाओ पीडीआर और भारत शामिल हैं। वार्ताओं का चौथा दौर अक्तूबर, 2007 को गोवा में मंत्रीमंडलीय कांफ्रेंस के द्वितीय सत्र में आयोजित किया गया। वार्ताओं के चौथे दौर को आगे बढ़ाने के लिए क्रमश: 15 दिसम्बर, 2009 और 13-14 दिसम्बर, 2010 को सिओल, दक्षिण कोरिया में मंत्रीमंडलीय परिषद की तीसरी बैठक और स्थायी समिति की 35वें सत्र की बैठक आयोजित की गई।

चुनौतियां तथा दृष्टिकोण

दृष्टिकोण

7.77 भारत के व्यापार क्षेत्र की संभावनाएं वर्ष 2010-11 (अप्रैल-दिसम्बर) में 29.5 प्रतिशत की अच्छी संवृद्धि तथा दिसम्बर 2010 में 36.4 प्रतिशत की मज़बूत वृद्धि के साथ उज्जवल हो गई हैं। तथापि, इस उज्जवल तस्वीर को विश्व व्यापार में हालिया घटनाक्रमों के कारण संतुलित किया जाना है, यद्यपि ये घटनाक्रम वर्तमान में अस्थायी स्वरूप के ही हैं। हालांकि विश्व पण्यवस्तु व्यापार में 2010 के प्रथमार्ध में तेज़ी आई, मूल प्रभाव के कारण तथा राजकोषीय प्रेरण के समाप्त हो जाने के कारण वर्ष 2010 की तीसरी तिमाही में व्यापार मंद हो गया था। वर्ष 2010 के पिछले कुछ महीनों में भारत के प्रमुख कारोबारी भागीदारों के निर्यातों तथा आयातों में वृद्धि भी संतुलित हो गई है। विशेष रूप से, यूरोपीय संघ की आयात वृद्धि में पूर्ण तेज़ी आने से पूर्व ही इसमें ह्रास हो रहा है, जुलाई तथा सितम्बर 2010 में यह गिरकर क्रमश: 7.8 प्रतिशत तथा 6.1 प्रतिशत के निम्न स्तर पर पहुंच गई थी तथा अक्टूबर और नवम्बर 2010 में तेज़ हो कर क्रमश: 9.3 प्रतिशत और 12.6 प्रतिशत हो गई। 2010 की चौथी तिमाही में यूरो क्षेत्र की परिधि में वित्तीय अस्तव्यस्तता के नए झटकों के उभरने के साथ कुछ समय के लिए ई यू में यह स्थिति जारी रहेगी। हांककांग, संयुक्त राज्य अमरीका, जापान तथा सिंगापुर जैसे अन्य बाजारों में भी ह्रास दर्ज किया गया।

7.78 आयात पक्ष में, मध्य पूर्व में नई गड़बड़ी फैल रही है जो तेल कीमतों के (ब्रेंट), जो 95 अमरीकी डालर प्रति बैरल के आसपास मंडरा रही थी; कुछ समय के लिए 100 अमरीकी डालर के स्तर को पार करने तथा स्वर्ण कीमतों के 7 दिसम्बर 2010 को 1423 अमरीकी डालर प्रति ट्राय औंस के चरम स्तर पर पहुंचने के पश्चात् 28 जनवरी 2011 को 1341 अमरीकी डालर प्रति ट्राय औस पर स्थिर होने में परिणामी हो रही है। यद्यपि व्यापार घाटा क्षेत्र की चिंताएं पिछले पांच महीनों में निर्यातों में तेज़ी आने तथा आयातों में 2010-11 के पिछले छ: महीनों में धीमापन आने से मंदित हो गई हैं, स्थिति पर नजर रखी जानी आवश्यक है। तथापि, सेवा व्यापार के निवल अधि शेष में ह्रास चालू खाता घाटा क्षेत्र के लिए चिंता का विषय है।

चुनौतियां

7.79 संकट का सफलतापूर्वक सामना करने के पश्चात्, भारत के लिए व्यापार मोर्चे पर अल्पावधि चुनौतियां निर्यात संवद्धि की गति को त्वरित करने तथा उसका अनुरक्षण करने एवं यह सुनिश्चित करने से संबंधित है कि व्यापार संवृद्धि क्षेत्र की मामूली सी धूमिल संभावनाएं सुधार कार्य सूची के मार्ग में न आएं। भारत तथा अन्य देशों द्वारा प्रेरक उपायों को क्रमिक रूप से वापस ले लिए जाने में भारत के बढ़ते निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। तथापि यूरो ज़ोन की परिधि में वित्तीय गड़बड़ी तथा मध्यपूर्व में अस्तव्यस्तताओं के किसी भी अनुवर्ती प्रभाव के बारे में सतर्क रहना आवश्यक है। समान रूप से महत्वपूर्ण है नवीन संरक्षणात्मक उपायों से सावधान रहने की आवश्यकता। यद्यपि इनमें से अधिकांश समाप्त हो रहे हैं, पहले से ही सुव्यवस्थित किए गए उपायों को शीघ्र समाप्त किया जाना आवश्यक है। भारत को इन व्यापार विरूपण उपायों को शीघ्र वापस लिए जाने के संबंध में द्विपक्षीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपनी आवाज़ उठानी होगी तथा साथ ही शेष उपायों के लिए समाप्ति खंडों पर भी जोर देना होगा। अंतर्देशीय क्षेत्र में मुद्रास्फीति

बॉक्स 7.6 : व्यापार नीतिगत सुधार : कुछ मध्यम और दीर्घावधिक चुनौतियां

मध्यम और दीर्घावधि में भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां निम्नलिखित हैं:

विश्व व्यापार में एक प्रमुख भागीदार बनने की चुनौती : भारत के लिए इसके आकार के अनुरूप विश्व में भागीदारी हासिल करने की चुनौती है। 2002-03 से 2007-08 तक अपनी निर्यात वृद्धि में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्राप्त करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के बावजूद, भारत ने विश्व व्यापार में हिस्से की दृष्टि से अधिक प्रगति नहीं की है। 1954 तक जहां भारत का निर्यात चीन की अपेक्षा अधिक था उसके बाद उसने पिछड़ना शुरू किया। 1990 में विश्व निर्यात में चीन और भारत का हिस्सा क्रमश: 1.8 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत था और 2009 में उनका हिस्सा क्रमश: 9.7 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत था। यदि भारत विश्व निर्यात में चीन के हिस्से का कम से कम आधा भी हासिल कर सके तो इसके रोजगार और विनिर्माण गतिविधि पर बेतहाशा प्रभाव होगा। व्यापार नीतिगत उपायों,, कुछ बाजारों और उत्पादों पर ध्यान केन्द्रित करने, व्यापार सुगमीकरण, टैरिफ सुधारों आदि ने जहां कुछ हद तक मदद की है वहीं यदि भारत को विश्व निर्यात में महत्वपूर्ण हिस्सा हासिल करना है तो बहुत अधिक प्रयासों की आवश्यकता होगी।

भारत के निर्यात के वास्तविक विविधीकरण की चुनौती : भारत ने जहां पिछले गत वर्षों के दौरान अपने निर्यात बास्केट तथा निर्यात बाजारों में विविधता लायी है वहीं वैश्विक मांग के अनुरूप पर्याप्त विविधीकरण नहीं हो पाया है। इसे छह अंकीय एचएस स्तर पर विश्व के शीर्ष 100 आयातों से भारत के निर्यात का मिलान करने पर देखा जा सकता है। पीसीटीएएस आंकड़े 2010 (2008 के आंकड़े) पर आधारित कवायद यह दर्शाती है कि वैश्विक मांग के इन शीर्ष मदों में भारत की मौजूदगी हीरे और आभूषण, खली, टी शर्ट, पुरूषों/लड़कों के ट्राउजर्स, फ्लैट रोल्ड लौह उत्पाद और मक्का जैसी कुछ मदों को छोड़कर नगण्य है। विश्व के शीर्ष 100 आयातों में अनेक इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीकल मदें (तीन ई) हैं जहां भारत की मौजूदगी नगण्य है।

निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की चुनौती: भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को न केवल चीन, और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों बल्कि नए उभरते हुए एशियाई देशों, बंगलादेश जैसे कम विकसित देशों वियतनाम जैसे छोटे देशों से टेक्सटाइल जैसी मदों में चुनौती मिल रही है। वृहत स्तर पर, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता के दो प्रमुख निर्धारक तत्व विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में परिलक्षित मुद्रास्फीति हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, 2010-11 के दौरान अब तक 6-मुद्रा और 36 मुद्रा आरईईआर की घट-बढ़ के बीच एक सुस्पष्ट भिन्नता है। छह मुद्रा आरईईआर जहां 16 से 20 प्रतिशत तक आधार स्तर से ऊपर बना रहा जो इन अर्थव्यवस्थाओं में उच्चतर मुद्रास्फीति को दर्शाता है वहीं 36 मुद्रा आरईईआर मुख्यतया आधार स्तर से नीचे या उसके आस पास रहा जो यह दर्शाता है कि भारत में मुद्रास्फीति विकासशील देशों में इसके व्यापारिक भागीदार देशों में प्रचलित स्तरों से तुलनीय अथवा नीचे रही है। इन देशों की मुद्राओं की सांकेतिक विनिमय पर अधिमूल्यन/अवमूल्यन की मात्रा में भी अंतर था जैसाकि 36 मुद्रा सूचकांक से 6 मुद्रा सूचकांक को हटाने के बाद प्राप्त 30 मुद्रा आरईईआर में परिलक्षित होता है। यदि सकारात्मक मुद्रास्फीति विभेदक जारी रहते हैं और कुछ देशों में उनके निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अल्प मूल्यांकित विनिमय दरों का प्रयोग करने की प्रवृत्ति और बढ़ती है तो भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता दबाव में आ सकती है। सूक्ष्म स्तर पर निर्यातों में उच्च लेनदेन लागत जैसे मुद्दे हैं। वाणिज्य विभाग की हाल की रिपोर्ट 'निर्यात में लेनदेन लागत पर कृतिक बल' भी इस मुद्दे को उजागर करती है। विश्व बैंक की ''डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट का हवाला देते हुए इसमें कहा गया है कि भारत से एक कंटेनर का निर्यात करने में 17 दिन लगते हैं और इसमें 945 अमरीकी डालर प्रति कंटेनर की लागत आती है जिसकी तुलना में मलेशिया और चीन में क्रमश: 450 अमरीकी डालर और 500 अमरीकी डालर की लागत आती है। डेनमार्क, ब्राजील, मेक्सिको और चीन उनके देशों से कंटेनर का निर्यात करने में क्रमश: 5 दिन, 12 दिन, 14 दिन और 21 दिन लेते हैं। रिपोर्ट में लेनदेन लागत का लगभग 13 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें कार्रवाई के लिए 44 मुद्दों को चिह्नित किया है जिसमें से 21 मुद्दों को कार्यान्वित किया जा चुका है और 11 मुद्दों पर कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। 21 मुद्दों और 2 अन्य मुद्दों के कार्यान्वयन से लेनदेन की लागत 2100 करोड़ रुपए (लगभग 467 मिलियन अमरीकी डालर) कम होने की संभावना है। लेनदेन की लागत को कम करने के आगे के प्रयासों से भारत की निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ सकती है।

टैरिफ सुधारों से संबंधित चुनौतियां

भारत क्रमिक रूप से अधिकतम सीमाशुल्क दरों को कम कर रहा है। अधिकतम शुल्क में गिरावट से राजस्व संग्रहण में अत्यधिक कमी की आशंका निर्मूल साबित हुई है। शुल्क में कटौतियों से न तो घरेलू विनिर्माण क्षेत्र प्रभावित हुआ है और न ही इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है, जैसे कि कईयों द्वारा पूर्वानुमान लगाया जा रहा था। आंकड़े दर्शाते हैं कि क्रमिक शुल्क कटौतियों से सीमा शुल्क संग्रहण बढ़ते हैं। तथापित अधिकतम दर तथा कुल शुल्क दोनों के लिए आसियान से तुलनीय स्तरों पर पहुंचने के लिए न्यूनतम राजस्व हानि सहित साहसिक टैरिफ सुधारों की आवश्यकता है (बॉक्स 7.5 भी देंखे)। टैरिफ सुधारों का एक क्षेत्र सीमाशुल्क छूटों और निर्यात संवर्धन योजनाओं से संबंधित है। सकल कर संग्रहण के प्रतिशत के रूप में परित्यक्त राजस्व का स्तर उच्च बना हुआ है जिसमें सभी परिकल्पित राजस्व का आधे से अधिक परित्यक्त खाते में चला जाता है। बदतर स्थिति यह है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान यह बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। वित्तीय वर्ष 2009-10 में परिकल्पित शुल्क का केवल 41.7 प्रतिशत संग्रहित किया गया जिसकी तुलना में 2008-09 और 2007-08 में यह क्रमश: 44.6 प्रतिशत और 51.1 प्रतिशत था। विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के कारण काफी बड़ी मात्रा में राजस्व का त्याग किया जाता है। 2010-11 में विदेशी व्यापार नीति 2009-14 (एफपीएस/एफएमएस/वीकेजीयूवाई) के अंतर्गत योजनाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार तथा निर्यातों में तेजी के साथ-साथ ड्यूटी इनटाइटलमेंट पासबुक (डीईपीबी) योजना में निर्यात संवर्धन दरों में सुधार के कारण परित्यक्त राजस्व 50,000 करोड़ रुपए से भी अधिक बना रहेगा। अंतिम प्रयोक्ता छूटों से राजस्व हानि भी बढ़ते आयात के साथ बढ़ जाएगी।

काफी बड़ी विभिन्न योजनाओं विभिन्न योजनाओं के मामले में जवाबदेही का भी प्रश्न है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जहां विशेषरूप से इस समय कुछ छूटों की आवश्यकता है वहीं इन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाकर और उन्हें परस्पर मिलाकर परित्यक्त शुल्क कम करने की गुंजाइश है। एक ऐसा उदाहरण निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु (ईपीसीजी) योजना से संबंधित है। सामान्य पूंजीगत वस्तुओं के आयात शुल्क में निरंतर कमी किए जाने से कुल पिछले 5 वर्षों के दौरान कुल ईपीसीजी में विभेदक 35.4 प्रतिशत से कम होकर 21.5 प्रतिशत पर आ गया

(जारी.....)

बॉक्स 7.6 : व्यापार नीतिगत सुधार : कुछ मध्यम और दीर्घावधिक चुनौतियां

है। सभी पूंजीगत वस्तुओं के लिए आयात शुल्क में एक और कमी करके इसे सामान्य ईपीसीजी के लिए निर्धारित तीन प्रतिशत के स्तर पर लाने से राजस्व हानि से बचने में मदद मिल सकती है और निर्यात संवर्धन योजनाओं को युक्तिसंगत बनाने में एक बड़ा कदम हो सकती हैं। यह आमतौर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र और विशेष रूप से आयात विनिर्माण के आधुनिकीकरण हेतु पूंजीगत वस्तुओं के आयात के लिए सीधे उत्प्रेरक का काम भी करेगा।

सफल डब्ल्यूटीओ वार्ताओं के न होने की स्थिति में एफटीए/व्यापक आर्थिक सहयोग करारों से संबंधित चुनौतियां: विश्व में एफटीए के प्रसार को 'स्पाघेटी बाउल' के रूप में जाना जाता है जिसमें टैरिफ भिन्नताओं और मूल देशों के जटिल नियमों के आधार पर व्यापार विभिन्न देशों के बीच एक जटिल तरीके से फैला हुआ है। हाल के वर्षों में भारत को अनेक क्षेत्रीय और द्विपक्षीय समूहों का भाग है। भारतीय निर्यात के लिए जहां इन एफटीए से लाभ हैं वहीं कुछ मामलों में भागीदार देशों को लाभ कहीं अधिक हैं जिसमें भारत से वृद्धिशील निर्यातों के निवल लाभ कम अथवा ऋणात्मक हैं। एफटीए से प्रतिलोमित शुल्क ढांचे का एक नया प्रकार तैयार होता है जिसमें अन्तिम उत्पादों के लिए शुल्क गैर-एफटीए देशों से आयातित पूर्व-अवस्था कच्ची सामग्रियों के लिए शुल्कों की तुलना में एफटीए भागीदारों से कमतर होता है। यह स्थानीय विनिर्माण जो प्रतिलोमित शुल्क ढांचा आयाम के कारण एफटीए आयात की तुलना में प्रतिस्पर्धी नहीं है, के लिए हतोत्साही कारक के रूप में कार्य करता है। उदाहरण के लिए, भारतीय टीवी सैट के लिए सामान्य सीमाशुल्क 10 प्रतिशत है, परन्तु थाईलैंड और सिंगापुर से निर्यात के मामले में मूल अपेक्षा के नियम के अधीन शून्य शुल्क है। कृषि मदों में समान मामले हैं। उदाहरणार्थ सुपारी पर 100 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क है। परन्तु भारत-श्रीलंका एफटीए और दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार के अंतर्गत श्रीलंका से और म्यांमार, भूटान और नेपाल जैसे एफटीए भागीदारों से आयात के लिए यह शुल्क शून्य है अथवा विभिन्न स्तरों पर रियायती न्यून दर है। यह कुछ क्षेत्रों को प्रभावित कर सकता है जो आजीविका के लिए मुख्य रूप से सुपारी की खेती पर निर्भर करते हैं। सुपारी उत्पादों पर कुछ राज्यों के प्रतिबंध से मांग पहले ही बहुत अधिक गिर गई हैं। कुछ उन मदों, जिन्हें राज्यों द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, के लिए एफटीए के अधीन रियायती शुल्कों पर आयात की अनुमति देने पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। एफटीए/सीईसीए से संबंधित नीतिगत चुनौती में घरेलू क्षेत्र की विशिष्ट चिन्ताओं का ध्यान रखा जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफटीए प्रभावित न हो इसके बजाय उन्हें उच्चतर व्यापार विशेषरूप से भारत से उच्चतर निवल निर्यात का जरिया बनाना चाहिए।

सेवा व्यापार से संबंधित चुनौतियां: सेवा व्यापार एक उन्मुक्त क्षेत्र है जिसमें प्रर्याप्त अवसर और चुनौतियां हैं। सेवाओं में एफडीआई को उदार बनाकर क्योंकि बहुराष्ट्रीय मूल फर्मों के सहायक कंपनियों के साथ अंत:फर्म व्यापार की प्रवृत्ति के चलते एफडीआई अन्तर्प्रवाहों और सेवाओं में व्यापार का निकट का संबंध है; नौवहन और दूरसंचार में सेवाओं में करों को युक्तिसंगत बनाकर; सरलीकरण करारों के साथ आगे बढ़कर; लाइसेंसिंग अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं, तकनीकी मानकों और विनियामक पारदर्शिता जैसे घरेलू विनियमों को कारगर बनाकर जिससे सेवाओं की वृद्धि और निर्यात में सहायता मिल सकती है; और बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय वार्ताओं में सेवाओं पर ध्यान केन्द्रित करना जारी रखकर सेवाओं में व्यापार के लिए एक अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सकता है। इनके साथ-साथ सेवाओं का व्यवास्थित विपणन, सेवाओं के एक पोर्टल की स्थापना करके बाजार सूचना का संग्रहण और प्रसार, सेवा डाटा प्रणाली को सुप्रवाही बनाकर और संलिप्त विभिन्न एजेन्सियों द्वारा एक अधिक केन्द्रित, समन्वित और सांमजस्यपूर्ण नीति से सेवा क्षेत्र को आगे ले जाने में मदद मिल सकती है। (अध्याय 10 भी देखे)

की चिंताओं के जारी रहने का अर्थ यह भी होगा कि व्यापार नीति उपायों का आगामी राजकोषीय वर्ष में मुद्रास्फीति का समाधान करने हेतु और परीक्षण किया जा सकता है। इससे पहले से ही विक्षत कृषिय निर्यात क्षेत्र के निर्यात और अपरक्षित हो सकते हैं। इसने तदर्थ उपायों के बाज़ार शीघ्र चेतावनी प्रणालियों वाले-प्रणालीबद्ध मुद्रास्फीति समाधान प्रक्रम का गठन आवश्यक बना दिया है।

7.80 भारतीय व्यापार क्षेत्र में अनेक विरोधाभासों के परिप्रेक्ष्य में मध्यम से दीर्घावधि में चुनौतियों को देखा जाना होगा (बॉक्स 7.6 भी देंखे)। भारत जहां विश्व व्यापार वार्ताओं में एक सक्रिया भागीदार और विश्व व्यापार नीति का नियन्ता बन रहा है, विश्व व्यापार में यह अभी भी एक छोटा भागीदार है। जहां एक ओर यह नए क्षेत्रों में बाजारों तक पहुंच बना रहा है और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ा रहा है, वहीं कुछ पारम्परिक क्षेत्रों में बाजार और प्रतिस्पर्धात्मकता पर इसकी पकड़ कम हो रही है। भारत ने जहां उच्च हिस्सेदारियों और उच्च वृद्धि वाले कुछ गतिशील पदार्थों के निर्यात में कुछ प्रगति की है, यह उन कुछ बड़ी मदों, जो वैश्विक मांग के शीर्ष पर हैं, के व्यापार में वास्तविक छाप छोड़ने में समर्थ नहीं रहा है। अत: जहां व्यापार में भारत के लिए सीमाएं असीम हैं, वहीं चुनौतियां भी उतनी ही विकट हैं।